Kalrav July 2026_Kalrav 8/8/2026 11:46 AM Page 1

मूल्यः ₹10.00

जुलाई, 2026

कलरव

KALRAV

पावन अवधपुरी का अ-पावन सर्ग

Kalrav July 2026_Kalrav 8/8/2026 11:46 AM Page 2

Three Unique Dailies For Everyone In The Family

AAJ KA ANAND	SANDHYANAND	Life 365
Hindi Daily: Published Since 41 years	Marathi Daily : Published Since 20 years	English Daily : Recently Lannched, Unique Daily

Aaj Ka Anand Papers Ltd., (Since 1971)

Kalrav July 2026_Kalrav 8/8/2026 11:46 AM Page 3

RNI-UPHIN-2006/18176

सच और साहस की थपकी का जुलाई, 2026

कलरव

ताकि बना रहे अहसास KALRAV

वर्ष : 20 अंक : 11

संपादक
अनिल तिवारी

प्रबंध संपादक
विक्रम उपाध्याय

कार्यकारी संपादक
वर्षा सिंह

उप संपादक
संध्या शुक्ला

विशेष संवाददाता
नचिकेता पटनायक
संजय कुमार

फोटो - संपादक
चमन गौतम

साज-सज्जा
राधेश्याम

कानूनी सलाहकार
कुंअर जयसिंह

(उपरोक्त सभी पद अवैतनिक हैं)

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक शोभा तिवारी द्वारा एबीएम ग्राफिक्स, सी-440, सेक्टर-10, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, (उत्तर प्रदेश) व डीटी प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, माजरा, देहरादून से मुद्रित तथा 93ए, अरावली अपार्टमेंट, सेक्टर-52, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से प्रकाशित।

कार्यालय: सी-288, सेक्टर-10
नोएडा, गौमतबुद्धनगर, यू.पी.
फोन: 0120-6545602
E-mail : kalarvms@rediffmail.com
Website: www.jankalrav.com

सौजन्य: सहयोग
707, पत्रकार विहार, इंदिरापुरम,
गाजियाबाद

अनुक्रम

06 बड़ों को बचाने के लिए छोटों की 'बलि'

10 राम के नाम पर लूट का बढ़ता दायरा

14 चढ़ावा चोरी की चर्चा के बीच समय पूर्व चुनाव की अटकलें!

16 चढ़ावा विवाद भाजपा के लिए चुनौती बन गया है तो सपा...

18 न्यास का वेटिकन न्याय- मजनूं को बुरा कहती है लैला मेरे आगे...

21 राम के चिरई-राम के खेत, खाऽल चिरई भर-भर पेट

20 समग्र हिंदुत्व की राह पर भाजपा

26 साधो, देखो जग बौराना!

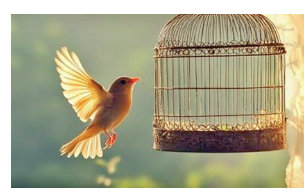

29 जंजीरें

30 ढुलमुल वांगचुक यानी थाली के बैंगन

32 घोषित इमरजेंसी बनाम अघोषित आपातकाल

वंचक भगत कहाई राम के...

अनिल तिवारी

भगवान है या भगवान नहीं है का विमर्श हमेशा से रहा है। भगवान के होने का कोई ठोस आधार अभी तक मनुष्य जाति को नहीं प्राप्त हुआ है, ठीक उसी तरह भगवान के न होने का भी कोई तार्किक, वैज्ञानिक, सर्वमान्य प्रमाण आज तक कोई आदम नहीं दे सका है। यह मामला पूरी तरह से 'उद्धौ मन माने की बात'का है। मानो तो शिव, ना मानो तो पत्थर।

वेदों, उपनिषदों, धर्म शास्त्रों और तमाम तरह के परिमाणों, प्रमाणों के आधार पर ऋषियों मुनियो चिंतकों और यहां तक कि आदि गुरु शंकराचार्य ने भगवान के व्यापकता की झलक अपने-अपने दृष्टिकोणों में नितांत दार्शनिक भाव से दी है। लेकिन जिन लोगों ने भगत सिंह का लेख ' मैं नास्तिक क्यों हूं, पढ़ा है, भगवान के बारे में उनकी धारणाएं कुछ भिन्न है। इस क्रम में लोकायत दर्शन, ज्योतिबा फुले या पेरियार रामास्वामी का लेखन अनुभव कुछ और अलग किस्म का है।

दुनिया भर में भगवान और भगवानों का धर्म अनादि काल से चर्चा और चिंतन का विषय रहा है। सभी धर्म की सामान्य मान्यता है कि भगवान ने ही दुनिया को गढ़ा है। इतिहास साक्षी है सभी धर्मों ने समय-समय पर अपनी सुविधा और सहूलियत के हिसाब से भगवानों का आविष्कार भी किया है और उनका अनुष्ठान भी किया है। समय विशेष पर भगवानों के मनुष्य रूप धरने की कथाएं हैं तो मनुष्यों के भी देव बनने की अनंत कथाएं हमारे वांग्मय में भरी पड़ी है।

संसार को चलायमान रखने के लिए सर्जक, पालक और संहारक सिद्धांत बहुधा स्वीकृति प्राप्त है। सामान्य बुद्धि कहती है कि अगर कोई पालक है तो फिर दुनिया में घोर भूखमरी कैसे हैं? जिस भगवान ने दुनिया बनाई उसी के मंदिरों में चोरी डकैती जैसे कुकृत्य क्यों कर होते हैं?

भगवान के घर में चोरी और डकैती का एक बड़ा उदाहरण अयोध्या का राम मंदिर तो बना ही है, अब रोज मंदिरों में चोरी- डकैती के उदाहरण सामने आ रहे हैं। वैष्णोदेवी मंदिर में 550 करोड़ की गड़बड़ी सामने आई है। केदारनाथ- बद्रीनाथ मंदिर की व्यवस्था पर भी प्रश्नचिह्न उठे हैं। कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। गुजरात के अंबाजी मंदिर से नकदी चोरी की खबर आई है। रायबरेली के कई मंदिरों से भगवान की मूर्तियां चोरी हो गई हैं। मध्य प्रदेश के सात जिलों में मंदिर की संपत्तियां हड़पने की खबर भी है। किसी ने मंदिर की फसल बेचकर रुपए जेब में रख लिये हैं।किसी मंदिर के महंत की गद्दी हथियाने के लिए तीन- तीन वसीयतें सामने आ गई हैं। अनेक संत महंत मंदिर की संपत्ति का किराया खा रहे है और यह तब है, जब इन मंदिरों के संरक्षक की भूमिका में वहां के कलेक्टर या एसडीएम हैं। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे में जो आज हो रहा है, उसके ये चंद से भी चंद उदाहरण हैं।

भगवान के घर में चोरी और डकैती का एक बड़ा उदाहरण अयोध्या का राम मंदिर तो बना ही है, अब रोज मंदिरों में चोरी- डकैती के उदाहरण सामने आ रहे हैं। वैष्णोदेवी मंदिर में 550 करोड़ की गड़बड़ी सामने आई है। केदारनाथ- बद्रीनाथ मंदिर की व्यवस्था पर भी प्रश्नचिह्न उठे हैं।

आप समझ सकते हैं कि इन चोरियों के पीछे कितने स्तरों पर कितनी तरह के चोर सक्रिय हैं

Kalrav July 2026_Kalrav 8/8/2026 11:46 AM Page 5

और खबर छपने और जांच होने से कोई डरेगा नहीं, किसी पर कोई खास असर भी नहीं पड़ेगा। इनमें से कुछ को जेल हो गई तो भी नये चोर पैदा हो जाएंगे। इनसे शातिर और बड़े चोर पैदा हो जाएंगे और कई बड़े वकील इनमें से अनेक चोरों को अदालत में ईमानदार साबित करवा लेंगे।जब राजनीतिक दलों की वाशिंग मशीन बड़े बड़े भ्रष्टों को धोकर उजला कर सकती है तो क्या और वाशिंग मशीनें अलग-अलग जगहों पर नहीं हैं?और क्या कोई वाशिंग मशीन राजनीतिक गिरोहों की पहुंच से दूर है?

शहीदे आजम भगत सिंह की बातों को माने तो ईश्वर हुआ होता तो ये सब डरते, हालांकि ऊपर से ये सब ईश्वर विश्वासी हैं। घर से निकलते हैं तो घर के मंदिर में प्रणाम करते हैं और रास्ते में जितने भी मंदिर पड़ते हैं वहां कार के अंदर से सिर नवाते हैं।जितने भी भ्रष्ट हैं,वे यह काम करना कभी नहीं भूलते!

ईश्वर होता तो लगभग रोज़ मंदिरों में मत्था टेककर फोटो खिंचवाने वाला इतना झूठा, दंभी और पाखंडी नहीं होता।उसे अच्छी तरह मालूम है कि ईश्वर नहीं है, जो है सत्ता है और धन है। सत्ता और धन ही असली ईश्वर है।ये छूट गया तो सब छूट गया। ईश्वर होता तो कोई भगवा वस्त्रधारी साधु इतना ज़ालिम और नफरती न होता, जो बात-बात पर गोली बंदूक से सबको डराने की कोशिश करता। कोई बाबा नफ़रत की गंगा बहाकर सत्ता की पूजा नहीं कर रहा होता। दरअसल कोई भगवान होता तो क्या कोई पंडा प्रतिदिन पाखंडपुराण पढ़ कर लोगों को डराता और उसका माल लूटता। सच तो यह है कि धर्म न होता तो परजीवियों की बहुत बड़ी जमात छप्पन भोग नहीं लगा रही होती। अब बहुत लोग मानने लगे हैं कि दुनिया में धर्म धंधा हो गया है, धर्म का विस्तृत बाजार बन गया है और आस्थावान श्रद्धालु जनता उपभोक्ता।

मेरे मन में भगवान को लेकर कोई संशय नहीं है। भगवान है तो भी ठीक, भगवान नहीं है तो भी ठीक। लेकिन भगवान के भक्तों और एजेंटों को लेकर मेरी राय बिल्कुल अलग है। आज के दौर में भी कुछ सचमुच भक्त होंगे, मगर मैं किसी जटाजूट बढ़ाए, नाना तरह के लोगों से घिरे कथित भगत देखता हूं तो संदेह से भर जाता हूं कि जरूर इसने किसी ग़लत काम को छुपाने के लिए यह आवरण ओढ़ रखा है। हालांकि मैं जानता हूं कि हरेक ऐसा नहीं होता।

धर्म हमेशा से पाखंडियों की सुरक्षित पनाहगाह रही है। कबीर ही नहीं, तुलसीदास की रचनाओं से भी कुछ -कुछ जाहिर हो जाता है। धर्म के हथियार से ही दलितों और स्त्रियों को आज तक कुचला गया है। आदिवासियों को जंगल और जमीन से बेदखल किया गया है। और आज भी किसी अब्दुल को सबक सिखाने, पीटने, उसकी नागरिकता छीनने, गोहत्या के नाम पर उसकी जान लेने में धर्म ही सहायक है वरना यह सब इतना आसान न होता।धर्म के बल पर ही आज आग मूती जा रही है और अंगारे खाये जा रहे हैं। वरना धर्म की रक्षा के लिए ही धरती पर उतरे भगवानों के मंदिरों में सरेआम चोरी डकैती की हिम्मत किसी की नहीं होती। हे राम! धर्म के नाम पर अधर्म करने वालों को सद्बुद्धि दीजिए।

धर्म हमेशा से पाखंडियों की सुरक्षित पनाहगाह रही है। कबीर ही नहीं, तुलसीदास की रचनाओं से भी कुछ -कुछ जाहिर हो जाता है। धर्म के हथियार से ही दलितों और स्त्रियों को आज तक कुचला गया है। आदिवासियों को जंगल और जमीन से बेदखल किया गया है। और आज भी किसी अब्दुल को सबक सिखाने, पीटने, उसकी नागरिकता छीनने, गोहत्या के नाम पर उसकी जान लेने में धर्म ही सहायक है वरना यह सब इतना आसान न होता।

Kalrav July 2026_Kalrav 8/8/2026 11:46 AM Page 6

बड़ों को बचाने के लिए छोटों की 'बलि'

■ टीम कलरव

देश दुनिया के लोक मन बिराजती तथा आठ कांडों से सुवासित अवधपुरी में राम मंदिर से चढ़ावा चोरी की कलंक कथा का 9 वां कांड उजागर होने से लोग हतप्रभ हैं। हिंदू आस्था के सबसे बड़े केंद्र पर बेधड़क खजाने की लूट, सोने, चांदी, हीरा-मोती, के बेसकीमती गहनों की चोरी,जमीनों की हेरा फेरी की संगठित साजिश से सभी श्रद्धालुओं को धक्का लगा है। उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं से प्राप्त दान के गबन के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

जनवरी 2024 में श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने के बमुश्किल ढाई साल बाद ही, अयोध्या का राम मंदिर बड़े वित्तीय घोटाले के केन्द्र में आ गया। जून 2026 में मंदिर को मिले दान में हेराफेरी के आरोप सामने आए। दो संस्थापक ट्रस्टियों ने इस्तीफा दे दिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया और आठ कर्मचारी गिरफ्तार किए गए। मंदिर का कामकाज संभालने के लिए एक 'प्रोफेशनल' सीईओ की तलाश के लिए एक सर्च कमेटी बन गई। एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट अब सार्वजनिक है। इसकी मुख्य बातों में दान के प्रबंधन की कमजोर निगरानी, नाकाफी सुरक्षा व्यवस्था, तलाशी के नियमों और बिना जेब वाली यूनिफॉर्म से जुड़ी मौजूदा व्यवस्थाओं में बदलाव, पैसा - गिनने की ऐसी प्रणाली जिसमें ट्रैक करने की सुविधा नहीं है, और अपर्याप्त निगरानी का मुद्दा शामिल हैं।

राज्य सरकार ने समय बढ़ाते हुए एसआईटी के लिए अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने को कहा है, हालांकि इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं। लेकिन गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ होती कार्रवाई जैसी दिखने वाली इस सारी गहमागहमी के बीच, कई सवाल हैं जिन पर अब भी सख्ती से पड़ताल होती नजर नहीं आती।

2019 में अयोध्या पर आए विवादित फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को राम मंदिर बनाने और उसका कामकाज संभालने के लिए ट्रस्ट बनाने का निर्देश दिया था। निर्देश में ऐसा तो नहीं कहा गया था कि ट्रस्ट 'प्राइवेट' होना चाहिए, लेकिन गृह मंत्रालय ने 2020 में जो ट्रस्ट बनाया, वह एक प्राइवेट ट्रस्ट था और उसमें विहिप, आरएसएस और उनसे जुड़े संगठनों के लोगों को संस्थापक ट्रस्टी के तौर पर शामिल किया गया। गृह मंत्रालय का कहना है और केन्द्रीय सूचना आयोग ने भी यह फैसला दिया है कि 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' एक स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था के तौर पर काम करता है, जिसे सरकार से कोई वित्तीय या प्रशासनिक मदद नहीं मिलती। इसी 'स्वायत्तता' की वजह से दिल्ली हाईकोर्ट और केन्द्रीय सूचना आयोग ने यह तर्क दिया है कि यह संस्था 'सूचना का अधिकार'

Kalrav July 2026_Kalrav 8/8/2026 11:46 AM Page 7

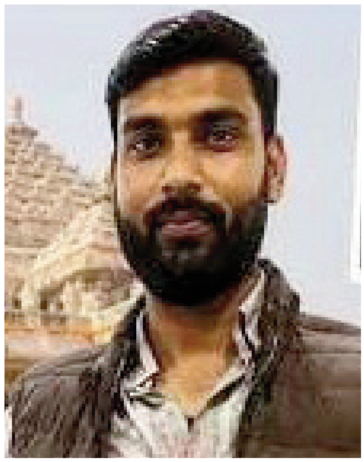

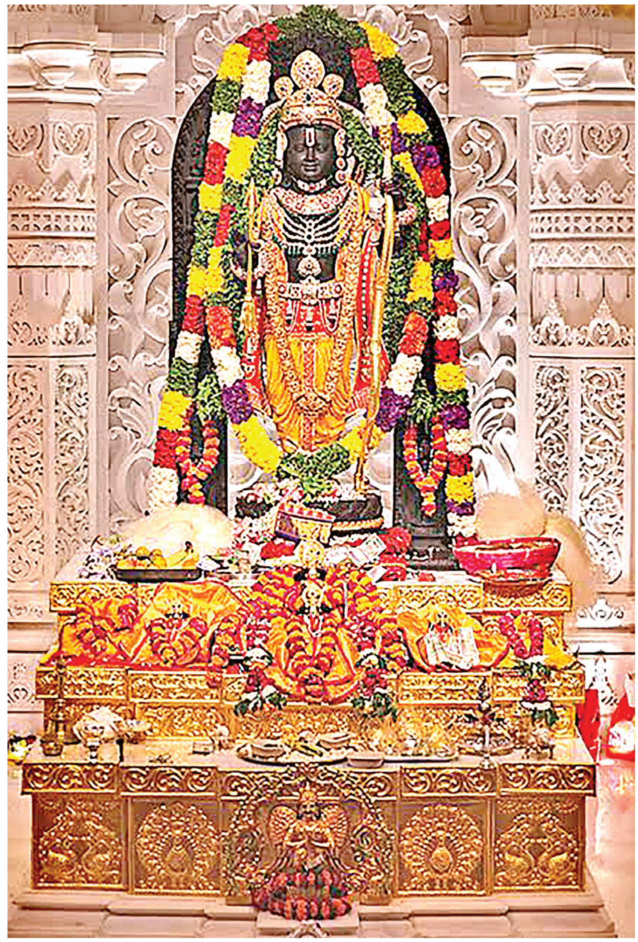

(आरटीआई) कानून के दायरे से बाहर है।

"एसआईटी के साथ पूर्ण सहयोग" का दिखावा करते हुए, ट्रस्ट के अधिकारियों ने जानकारी सुरक्षित रखने के लिए एसआईटी की स्वायत्त और स्वतंत्र स्थिति का फायदा उठाने की भरपूर कोशिश की है। वे अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारी से बच निकलने की जुगत लगा रहे और चल रही एसआईटी जांच को आड़ बनाकर मीडिया को भी इससे दूर रखने की हर कोशिश कर रहे हैं।

एसआईटी को दिए अपने बयानों में, ट्रस्ट के महासचिव चंपत बंसल (जिन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया) ने कथित तौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर दोष मढ़कर ट्रस्ट के अधिकारियों को चोरी की घटना से अलग करने की कोशिश की है। उनका तर्क है कि गिरफ्तार किए गए काउंटिंग एजेंट बैंक की ऑपरेशनल चेन ऑफ कमांड के तहत काम कर रहे थे और चोरी की घटना ट्रस्ट की निगरानी के बजाय 'प्राइवेट एजेंसी की देखरेख' में हुई थी।

केन्द्रीय सूचना आयोग के फैसलों का हवाला देते हुए ट्रस्ट लगातार यह तर्क देता रहा है कि चूंकि यह एक स्वतंत्र संस्था है, जिसका न तो सरकार के पास मालिकाना हक है और न ही सरकार इसे फंड देती है, इसलिए यह 'सूचना का अधिकार' (आरटीआई) कानून के तहत 'सार्वजनिक प्राधिकरण' नहीं है। इसी कानूनी सुरक्षा कवच का इस्तेमाल करते हुए, नागरिकों और पत्रकारों को मंदिर की रोजाना की आंतरिक बैलेंस शीट, लेजर एंट्री और खरीद अनुबंधों की जांच के लिए आरटीआई के तहत सवाल पूछने से भी रोकने में वे सफल रहे हैं।

दूसरी ओर, कानूनी जानकारों का तर्क है कि जब कोई धार्मिक संस्थान, जो सीधे लोगों से जुड़ा हो. किसी प्राइवेट ट्रस्ट के तौर पर काम करता है और कानूनी निगरानी के सामान्य दायरे से बाहर होता है, तो उसे भरोसेमंद ऑडिट सिस्टम के जरिये जांच के लिए खुला रहना चाहिए, क्योंकि आस्था भले ही 'निजी' हो. उसके नाम पर इकट्ठा किया गया पैसा जनता के बीच से ही आता है।

सार्वजनिक मंदिरों में दिए गए दान का प्रबंधन स्वायत्त या वंशानुगत ट्रस्टियों द्वारा ठीक से संचालित न किए जाने की स्थिति में अदालतें पहले भी दखल देती रही हैंः

चिदंबरम नटराज मंदिर मामले (2014) में, तमिलनाडु के

Kalrav July 2026_Kalrav 8/8/2026 11:46 AM Page 8

मशहूर नटराज मंदिर के वंशानुगत ट्रस्टियों (पोड्डु दीक्षितार) ने पूरी तरह से स्वायत्त प्रबंधन का दावा किया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हालांकि राज्य किसी मंदिर का स्थायी रूप से नियंत्रण नहीं ले सकता, लेकिन अगर सार्वजनिक चढ़ावे में बड़े पैमाने पर वित्तीय हेराफेरी या कुप्रबंधन का सबूत मिलता है, तो उसे दखल देने, खातों की ऑडिटिंग और ट्रस्टियों पर आपराधिक मुकदमा चलाने का अधिकार है।

श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर मामले (2020) में, त्रावणकोर के शाही परिवार ने मंदिर और उसके विशाल तहखानों पर निजी प्रबंधन का दावा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनके पारंपरिक अधिकार तो बरकरार रखे, लेकिन स्पष्ट तौर पर कहा कि किसी सार्वजनिक धार्मिक संस्थान को निजी जागीर की तरह नहीं चलाया जा सकता। कोर्ट ने खजाने की देखरेख और सख्त, पारदर्शी ऑडिटिंग मानक लागू करने के लिए एक स्वतंत्र प्रशासनिक समिति बना दी।

भारत के सामान्य टैक्स और प्रॉपर्टी कानूनों के तहत, जब कोई संपत्ति धार्मिक श्रद्धालुओं के किसी ऐसे समूह को समर्पित की जाती है, जिसकी पहचान निश्चित नहीं है, तो उसे अपने आप 'सार्वजनिक धार्मिक ट्रस्ट' (पब्लिक रिलीजियत ट्रस्ट) की कानूनी परिभाषा मिल जाती है।

चंपत बंसल और अनिल मिश्रा के 'नैतिक आधार' पर इस्तीफे को धार्मिक या नैतिक काम के बजाय एक सोची-समझी कानूनी चाल के तौर पर देखा जा रहा है। नैतिक जिम्मेदारी का हवाला देते हुए पद छोड़ने से बंसल और मिश्रा ने खुद को जबरदस्ती हटाए जाने से बचा लिया है।

तीर्थ क्षेत्र के दो ट्रस्टियों- महासचिव चंपत बंसल और सदस्य ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने 'नैतिक जिम्मेदारी' का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया, जबकि कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने खुद को बेगुनाह बताते हुए कहा कि वे पुणे में बैठते हैं, ट्रस्ट में बने रहे। कानूनी रूप से यह कहां तक सही है?

कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने अपने बचाव में कहा है कि वे पुणे में बैठते हैं और हर महीने के आखिर में सिर्फ ऑडिट किए गए खाते की समीक्षा करते हैं'। कानूनी जानकारों का कहना है कि इंडियन ट्रस्ट्स एक्ट, 1882 के तहत, नियुक्त कोषाध्यक्ष ट्रस्ट की संपत्ति की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। उनका तर्क है कि कोषाध्यक्ष भौगोलिक दूरी या व्यक्तिगत रूप से शामिल न होने का हवाला देकर कानूनी तौर पर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते।

अगर नकदी प्रबंधन की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में बुनियादी तौर पर खामियां थीं, और जिसकी वजह से नकदी गिनने वाले कर्मचारी बार-बार नोटों की गड्डियां अपनी जेबों और जूतों में छिपा लेते थे, तो इसके लिए कोषाध्यक्ष को आपराधिक लापरवाही का दोषी माना जा सकता है। भले ही वह खुद चोरी में आपराधिक रूप से शामिल नहीं थे, लेकिन सुरक्षित आंतरिक नियंत्रण या ऑडिटिंग सिस्टम लागू न कर

Kalrav July 2026_Kalrav 8/8/2026 11:46 AM Page 9

पाना भरोसे से जुड़ी जिम्मेदारियों (सिविल फिड्यूशरी ड्यूटीज) का उल्लंघन है।

चंपत बंसल और अनिल मिश्रा के 'नैतिक आधार' पर इस्तीफे को धार्मिक या नैतिक काम के बजाय एक सोची-समझी कानूनी चाल के तौर पर देखा जा रहा है। नैतिक जिम्मेदारी का हवाला देते हुए पद छोड़ने से बंसल और मिश्रा ने खुद को जबरदस्ती हटाए जाने से बचा लिया है। ट्रस्ट के संविधान के मुताबिक, जब कोई ट्रस्टी इस्तीफा देता है, तो उस पर कार्रवाई करके उसे मंजूर करना जरूरी होता है। इससे उन्हें प्रशासन से आसानी से हटने का मौका मिल जाता है, और ट्रस्ट को तकनीकी रूप से उन्हें किसी प्रशासनिक विफलता के लिए 'दोषी' नहीं ठहराना पड़ता।

ट्रस्ट इन दोनों के बचाव में तत्काल सार्वजनिक तौर पर सामने आया- कुछ सदस्यों ने तो उन्हें 'बेदाग' तक बताया और कहा कि उनसे महज 'लापरवाही वाली गलतियां' हुई थीं, लेकिन इस कदम का कड़ा कानूनी विरोध हुआ है।

इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री की गहन चुप्पी है। आखिर प्रधानमंत्री की इस चुप्पी का राज क्या है, जबकि उन्होंने तो मंदिर के उद्घाटन में बतौर 'यजमान' मुख्य भूमिका निभाई थी ?

ट्रस्ट बनाने की घोषणा संसद में प्रधानमंत्री ने ही की थी, उन्होंने ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में 'भूमि पूजन' किया था और जनवरी 2024 में मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा के समय 'यजमान' की भूमिका भी निभाई थी। वह इस धार्मिक स्थल के राजनीतिक महत्व को अच्छी तरह समझते हैं, फिर भी इस घोटाले पर उनकी चुप्पी रहस्यमय है।

अब असल हो या मनगढ़ंत, राम मंदिर से जुड़ी हर चीज का श्रेय प्रधानमंत्री को दिया जाता रहा है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या फैसले के लिए आधार/ तर्क तैयार करने का श्रेय भी उन्हें ही दिया गया। सबको पता है कि मंदिर और उसके ट्रस्टी बोर्ड में कौन होगा, यह असल में पीएमओ ही नियंत्रित करता है, भले ही वह रोजमर्रा के कामकाज से दूर रहता हो और आधिकारिक तौर पर खुद को इससे अलग दिखाता हो।

प्रधानमंत्री के भरोसेमंद सहयोगी नृपेंद्र मिश्र, जो उनके प्रथम कार्यकाल (2014-2019) में प्रधान सचिव भी थे, ट्रस्ट के पदेन सदस्य और राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं; और कोई शक नहीं कि वहां की हर गतिविधि पर उनकी पैनी नजर रहती है।

ट्रस्ट बनाने की घोषणा संसद में प्रधानमंत्री ने ही की थी, उन्होंने ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में 'भूमि पूजन' किया था और जनवरी 2024 में मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा के समय 'यजमान' की भूमिका भी निभाई थी। वह इस धार्मिक स्थल के राजनीतिक महत्व को अच्छी तरह समझते हैं, फिर भी इस घोटाले पर उनकी चुप्पी रहस्यमय है। आखिर माजरा क्या है? ■

Kalrav July 2026_Kalrav 8/8/2026 11:46 AM Page 10

राम के नाम पर लूट का बढ़ता दायरा

आलोक जयहिंद

हिंदू तीर्थ स्थलों के प्रमुख केंद्रों में लूट-खसोट का खेल धड़ल्ले से चल रहा है।अयोध्या और वाराणसी से लेकर उज्जैन, वृंदावन, केदारनाथ और बद्रीनाथ तक लूटपाट का एक ही ढर्रा सामने आ रहा है। मंदिरों के प्रबंधन में लगे लोग हिंदू आस्था की परवाह किए बगैर कुकृत्यों को सरेआम अंजाम देने में लिप्त बताए जा रहे हैं।

हमारे प्राचीन मंदिरों के आसपास की विशाल भूमि को हड़पने के लिए 'पुनर्विकास' का खेल खेला जा रहा है। निहित राजनीतिक स्वार्थ वाले इन जमीनों को मनमाने दामों पर उन्हीं ट्रस्टों को बेच रहे हैं जो इन मंदिरों का प्रबंधन संभालते हैं। काशी विश्वनाथ (वाराणसी), राम जन्मभूमि (अयोध्या), महाकालेश्वर (उज्जैन) या बांके बिहारी (वृंदावन) हो- यह विवाद महज कुछ छिटपुट आरोपों तक सीमित नहीं है।

विपक्षी दलों, धार्मिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और यहां तक कि हिन्दुत्व खेमे के कई अन्य गुटों ने प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों, मंदिर ट्रस्टों और नौकरशाहों पर निजी लाभ के लिए जनता की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। जमीनों की सट्टेबाजी, अपारदर्शी वित्तीय लेन-देन, व्यावसायीकरण और हजारों करोड़ का गबन हिन्दुत्व के इन प्रमुख केन्द्रों में सामने आ रहे घोटालों के मुख्य लक्षण बन गए हैं।

सबसे गंभीर आरोप अयोध्या में राम मंदिर का संचालन करने वाले 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' पर लगे हैं। मोटे अनुमान के मुताबिक, चंदे में करीब 200 करोड़ रुपये की हेराफेरी हुई, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि यह घोटाला 10,000 करोड़ रुपये से भी अधिक का है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि यह पैसा उन प्रभावशाली नेताओं तक पहुंचाया गया जिनके नामों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है।

यह परियोजना शुरू से ही विवादों में रही है। सबसे पुराने और शक्तिशाली रामानंदी संप्रदायों में से एक, 'निर्मोही अखाड़ा' ने विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) पर 1990 के

दशक की शुरुआत से भक्तों से प्राप्त 1,400 करोड़ रुपये से अधिक के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। आरोप था कि मंदिर निर्माण में खर्च के बजाय इस पैसे का उपयोग उनके अपने संस्थागत भवनों को बनाने और उनके नेताओं के राजनीतिक कद को बढ़ाने के लिए किया गया।

सर्वविदित है कि ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत बंसल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच वैचारिक पटरी नहीं बैठती थी। योगी आदित्यनाथ सही मौके के इंतजार में थे। 13 जून 2026 को उन्होंने एसआईटी के गठन का आदेश दिया। इसी दिन, राम मंदिर में निर्माण प्रभारी गोपाल राव के बारे में खबर आई कि वह सोने और चांदी की सिल्लियों से भरे बोरे लेकर ट्रेन पकड़कर रफूचक्कर हो गए। बाद में उन्हें बेंगलुरु में आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ देखा गया। बताया जाता है कि उनके भतीजे सोमेश आनंद अयोध्या से कर्नाटक तक सोने और चांदी के ये बैग लेकर गए थे।

इस बीच, विपक्षी दलों ने संदेहास्पद भूमि लेन-देन के आरोपों को और तेज कर दिया है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जांच कर रही एसआईटी को 11 भूमि सौदों से जुड़े दस्तावेज सौंपे हैं। यह टीम अब राम मंदिर के आयोजनों पर हुए खर्चों की जांच कर रही है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा समारोह (जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की थी) पर खर्च हुए 113 करोड़ रुपये और नवंबर 2025 में हुए ध्वजारोहण समारोह पर खर्च हुए 10.12 करोड़ रुपये शामिल हैं।

ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बताया कि अब तक केवल निचले स्तर के कर्मचारियों को ही गिरफ्तार किया गया है, जबकि 'घोटालों के लिए जिम्मेदार बड़े लोग' खुलेआम घूम रहे हैं।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सत्ताधारी भाजपा पर वाराणसी, वृंदावन और मिर्जापुर जैसे हिन्दू धार्मिक स्थलों की मौलिकता को नष्ट करने और उन्हें पर्यटन स्थलों में बदलने का आरोप लगाया है। राय का तर्क है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसी विकास परियोजनाओं की आड़ में प्राचीन धार्मिक इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया, इसका दायरा 3,000 वर्ग फुट से बढ़ाकर 5,00,000 वर्ग फुट कर दिया गया। उनका कहना है कि भाजपा नीत सरकार ने सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के बजाय व्यावसायीकरण को प्राथमिकता दी, जिससे उन समुदायों की आजीविका नष्ट हो गई है जो सदियों से इन पवित्र स्थलों की सेवा कर रहे थे।

ऐसा ही ढर्रा उज्जैन में देखा जा रहा है, जिसे 2028 में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ के मद्देनजर अगले धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में तैयार किया जा रहा है। इन तैयारियों के कारण महाकालेश्वर मंदिर के आसपास बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण शुरू हो गया है। पार्किंग सुविधाओं और 'उज्जैन महाकाल लोक कॉरिडोर' के लिए दुकानों, घरों और यहां तक कि एक दो सदी पुरानी मस्जिद को भी ध्वस्त कर दिया गया।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की इस भव्य घोषणा कि उनकी सरकार सिंहस्थ कुंभ के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 2,378 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करेगी, का किसान संगठनों और यहां तक कि आरएसएस समर्थित 'भारतीय किसान संघ' ने इतना कड़ा विरोध किया कि यादव को 17 नवंबर 2025 को इस अधिसूचना को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।

मुख्यमंत्री यादव और भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय के बीच का सार्वजनिक विवाद हाल ही में फिर सामने आ गया। जब मालवीय ने कथित तौर पर महाकाल मंदिर के ठीक बगल में 'यूटोपिया बॉटल एंड रिसॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड' के नाम पर 45,000 वर्ग फुट जमीन खरीदी, तो लोकायुक्त, आर्थिक अपराध शाखा और हाईकोर्ट में शिकायत की गई कि मंदिर की मौजूदा पार्किंग की जगह पर एक पांच सितारा होटल बनाने की तैयारी है। इसके जवाब में मालवीय ने आरोप लगाया कि यादव के दिसंबर 2013 में पद संभालने के बाद, उनके परिवार और उनकी रियल एस्टेट कंपनियों ने दो वर्षों में कम से कम 137 प्लॉट खरीदे जो 168 एकड़ से अधिक जमीन है।

भोपाल के एक राजनीतिक विश्लेषक ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, 'महाकाल लोक कॉरिडोर 1,200 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा है। विकास कार्यों के लिए सरकारी फंड से और 400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। नेताओं और नौकरशाहों का 35 फीसद का कमीशन ही 350 करोड़ रुपये बैठता है।

निर्माण कार्य इतना घटिया स्तर का है कि पिछले साल मंदिर परिसर में स्थापित की गई मूर्तियां और भित्तिचित्र एक ही जोरदार बारिश में ढह गए।'

सरकारों का कॉरिडोर बनाने का यह जुनून अब वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी कॉरिडोर के निर्माण और भूमि अधिग्रहण के लिए मंदिर के फंड से 500 करोड़ रुपये के उपयोग को हरी झंडी दे दी है। भूमि अधिग्रहण और शुरुआती निर्माण के लिए राज्य सरकार का अपना बजटीय आवंटन 762 करोड़ रुपये है।

अधिकारी 300 से अधिक संपत्तियों का सर्वेक्षण कर रहे हैं और प्रभावित निवासियों और लगभग 100 से अधिक दुकानदारों के साथ मुआवजे की राशि पर बातचीत कर रहे हैं, जिनकी दुकानें तोड़ी जानी

हैं। बांके बिहारी मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष नीरज गौतम का मानना है कि यह कॉरिडोर वाराणसी में जो हुआ उसी की पुनरावृत्ति होगाः 'इससे ब्रज की मूल संस्कृति ही मिट जाएगी।'

हालांकि सरकार का दावा है कि यह कॉरिडोर तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा में सुधार करेगा, लेकिन स्थानीय लोगों को डर है कि इससे वृंदावन की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी। हमारे धामों का जिस तरह कायाकल्प किया जा रहा है, उसे देखते हुए उनका डर निराधार नहीं। केदारनाथ और बद्रीनाथ में बहुमंजिला कंक्रीट की इमारतें खड़ी हो गई हैं, जो पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्र के लिए अनुपयुक्त हैं।

इन दोनों धामों में भी लूट-खसोट की स्क्रिप्ट के अलग-अलग रूप देखे गए। साल 2023 में, केदारनाथ के शिव मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर चढ़ाई गई 100 करोड़ रुपये की सोने की परत रातों-रात चोरी हो गई, जिसके दोषियों को पकड़ा नहीं जा सका। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और स्थानीय पुजारियों ने सार्वजनिक रूप से दावा किया था कि गर्भगृह से 228 किलोग्राम तक सोना गायब हो गया है। इसके बाद, जुलाई 2026 के पहले सप्ताह में एक और खुलासा हुआ-बद्रीनाथ धाम से मंदिर का चंदा गायब है। तब से एक मंदिर कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है, और यह राशि करोड़ों में होने की आशंका है।

वृंदावन भर में भूमि उपयोग नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन देखा जा रहा है। आश्रमों और मंदिरों के लिए आरक्षित सैकड़ों एकड़ भूमि पर व्यावसायिक इमारतें और लक्जरी होटल खड़े हो गए हैं। यह सब 'मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण' की नाक के नीचे हो रहा है जिसने इस खुले दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर की स्थिति भी ऐसी ही है। संत दिनेश 'फलाहारी' महाराज ने सार्वजनिक रूप से अयोध्या के राम मंदिर की तरह ही बड़े गबन का आरोप लगाया और मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। करपात्री परंपरा के सिद्ध संत राजू दास उदास है तथा हाल की घटनाओं को लेकर चिंता व्यक्त किया हैं। दुखी मन से कहा कि 'राम नाम की लूट' के लिए विदेश से भी लोग यहां खींचे चले आते हैं, लेकिन यहां तो 'राम के नाम पर लूट' होने लगी है। ■

चढ़ावा चोरी की चर्चा के बीच समय पूर्व चुनाव की अटकलें!

डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव समय से पहले कराए जाने की अटकलें जोरों पर है! हालांकि अयोध्या राम मंदिर से चढ़ावा चोरी के मामले उजागर होने के बाद आए ठीठकाव से थोड़ा असमंजस भी पैदा हुआ है, लेकिन हाल में हुए कई राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणामों से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी के चुनावी संतुलनकार जीत की लय को बरकरार रखने के लिए समय पूर्व चुनाव के लिए जमीन तैयार करने में जुटे हुए हैं। चुनाव के लिहाज से गठित नई कार्यकारिणी की घोषणा के बाद से ही सूबे के मुखिया अपने चिर परिचित समग्र हिंदुत्व को आगे कर लगातार जनता के बीच जा रहे हैं तथा मथुरा काशी का हवाला देकर विपक्षी दलों को सनातन विरोधी बताते हुए घेरने की कोशिश कर रहे हैं।

यूं तो वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में सभी राजनैतिक दलों ने अपनी चुनावी तैयारियों और मुद्दों को अंतिम रूप देना प्रारंभ कर दिया है, लेकिन सत्ताधारी भाजपा चुनाव को लेकर अत्यधिक उत्साहित है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हुई हानि की हर हाल में भरपाई के लिए पार्टी तमाम रणनीतिक कदम उठा रही है।इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बहुप्रतीक्षित कार्यकारिणी भी घोषित कर दी है। माना जा रहा है कि भाजपा की यह टीम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं केंद्रीय नेतृत्व की पसंद से चुनी गई है किन्तु इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी महती भूमिका है। भाजपा ने अपनी नई टीम में सामाजिक सन्तुलन साधने के साथ ही सपा के पीडीए व बसपा के ब्राह्मण कार्ड को रोकने का प्रबंध किया है। अब चुनाव केवल सामाजिक समीकरण के बल पर ही नहीं जीते जाते इसलिए भाजपा ने अपनी टीम की संरचना से यह भी स्पष्ट किया है कि वह चुनावी दंगल बूथ स्तर पर आकर ही लड़ेगी। भाजपा अब अपने बूथ प्रबंधन को सशक्त करने के लिए काम करेगी जिसके लिए प्रदेश की टीम को एकदम युवा व कर्मठ चेहरे दिए गए हैं। भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी में प्रवक्ताओं की टीम भी घोषित कर दी गई है और सोशल मीडिया प्रमुख की भी नियुक्ति की गई है क्योंकि अब प्रमुख राजनैतिक नैरेटिव युद्ध पारंपरिक और सोशल मीडिया दोनों पर लड़ा जाता है। चुनावी जंग जीतने में मीडिया व सोशल मीडिया भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पश्चिम बंगाल चुनावों में नैरेटिव युद्ध ने भाजपा की विजय में बड़ी भूमिका निभाई थी।

प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की नई टीम में सपा के पीडीए की धार कुंद करने का प्रयास किया गया है। राज्य में भाजपा का संगठन 6 क्षेत्रों में विभाजित है। इनमें पश्चिम नवाब सिंह नागर को, ब्रज क्षेत्र में पूरन

Kalrav July 2026_Kalrav 8/8/2026 11:46 AM Page 15

लाल लोधी तथा कानपुर क्षेत्र में राम किशोर साहू अध्यक्ष बने हैं। काशी क्षेत्र के अध्यक्ष अशोक चौरसिया बनाए गए हैं। अवध के क्षेत्रीय अध्यक्ष अवधेश द्विवेदी बने हैं। गोरखपुर क्षेत्र की कमान विनोद राय को मिली है जो भूमिहार हैं। प्रदेश में 19 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और इनमें भी ओबीसी वर्ग को प्राथमिकता दी गई है। 8 महामंत्रियों की सूची मे भी 4 ओबीसी वर्ग के हैं।

प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी के चयन में सामाजिक संतुलन के साथ-साथ क्षेत्रीय संतुलन साधने का प्रयास भी किया गया है। सपा छोड़कर भाजपा मे शामिल हुई पूजा पाल को प्रयागराज में जिम्मेदार दी गई है। एक समय प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद का आतंक था और उस पर पूजा पाल के पति राजू पाल की हत्या का आरोप था। भाजपा ने अपनी कार्यकारिणी के माध्यम से दलित गैर-जाटव समुदाय से पासी और कोरी समाज को भी साधने का प्रयास किया है। भाजपा ने कुशवाहा, मौर्य और सैनी समुदाय से तीन नेताओं को उपाध्यक्ष बनाया है जाट, कुर्मी, यादव और पाल समाज से भी उपाध्यक्ष बनाया गया ।

भाजपा की कार्यकारिणी से प्रतीत हो रहा है कि भाजपा के तरकश में अभी कई तीर छिपे हैं। यह बात तो तय हो गई है कि अब भाजपा समग्र हिंदुत्व की राजनीति करने जा रही है। भाजपा व संघ द्वारा अब प्रदेश में बंगाल की ही तरह 94 प्रतिशत हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने का प्रयास किया जाएगा।

भाजपा कार्यकारिणी की सूची आते ही सपा, बसपा व कांग्रेस की राजनीतिक हलचलें भी तेज हो गई है। यह चर्चा भी सुनी जा रही है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के चुनाव वर्ष 2026 के अक्टूबर- नवंबर में भी करवा सकता है क्योंकि आगे जनगणना का वृहद अभियान चलना है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल तथा असम सहित कई राज्यों के निकाय चुनावों में लगातार मिल रही सफलता से उत्साहित है और अपनी विजय का संवेग बनाए रखने के लिए के लिए विपक्ष को तैयारी के लिए समय नहीं देना चाहती। हालांकि राम मंदिर चंदा कांड ने प्रदेश में पार्टी को बैक फुट पर ला दिया है। लेकिन पार्टी के संतुलनकारों को यह यकीन है की समग्र हिंदुत्व के सहारे सब कुछ साधा जा सकता है, और इसके लिए जरूरी पहल भी की जा रही है। बताते हैं कि समयपुर चुनाव की योजना भी ऐसी ही पहल की कोई उपज है! ■

Kalrav July 2026_Kalrav 8/8/2026 11:46 AM Page 16

चढ़ावा विवाद भाजपा के लिए चुनौती बन गया है तो सपा के लिए बड़ा मौका

विनय जयहिंद

अयोध्या में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था। यह तीन दशक लंबे राम मंदिर आंदोलन की राजनीतिक और वैचारिक पराकाष्ठा थी। भाजपा का विश्वास था कि राम मंदिर आने वाले वर्षों तक उसके सबसे मजबूत राजनीतिक नैरेटिव का केंद्र बना रहेगा।

लेकिन प्राण-प्रतिष्ठा के ढाई वर्ष के भीतर ही राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे में कथित चोरी के आरोपों ने पूरे घटनाक्रम को एक अलग दिशा दे दी है। इस विवाद की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार बहस मंदिर निर्माण को लेकर नहीं है। सवाल मंदिर के प्रबंधन, पारदर्शिता और जवाबदेही पर उठ रहे हैं।

यही कारण है कि यह मामला 2021 के जमीन खरीद विवाद से अलग माना जा रहा है। उस समय विपक्ष के आरोपों को ट्रस्ट और भाजपा ने राजनीतिक हमला बताकर खारिज कर दिया था, लेकिन इस बार खुद उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी गठित की, ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज कराई, कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई और जांच का दायरा संस्थागत जिम्मेदारी तक पहुंच गया। 7 जून को समाजवादी पार्टी के नेता तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने पहली बार चढ़ावे में गड़बड़ी का आरोप लगाया। शुरुआती दौर में इसे राजनीतिक आरोप माना गया लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, मामला केवल विपक्ष के आरोपों तक सीमित नहीं रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 13 जून को तीन सदस्यीय एसआईटी गठित की और 19 जून को अयोध्या दौरे के दौरान सार्वजनिक रूप से कहा कि 'कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा,' यहीं से राजनीतिक विमर्श भी बदल गया। अब विपक्ष यह नहीं कह रहा है कि मंदिर नहीं बनना चाहिए बल्कि यह पूछ रहा है कि श्रद्धालुओं के दान की सुरक्षा और उसका हिसाब-किताब कैसे रखा गया।

राम मंदिर भाजपा की वैचारिक पहचान का सबसे मजबूत प्रतीक रहा है। मंदिर निर्माण को पार्टी अपनी सबसे बड़ी वैचारिक उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करती रही है। ऐसे में मंदिर प्रबंधन से जुड़ा कोई भी विवाद स्वाभाविक रूप से राजनीतिक असर पैदा करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए यह मामला और अधिक संवेदनशील है। गोरक्षपीठ राम मंदिर आंदोलन की प्रमुख शक्ति रही है। उनके गुरु महंत अवैद्यनाथ इस आंदोलन के अग्रणी नेताओं में शामिल थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी ने फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया, दीपोत्सव को वैश्विक पहचान दिलाई और रामनगरी के व्यापक विकास को अपनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल किया। इसलिए मंदिर प्रबंधन पर उठे सवाल सीधे सरकार की साख से जुड़ते दिखाई देते हैं, हालांकि भाजपा इस संकट को अवसर में बदलने की कोशिश कर रही है।

पार्टी का दावा है कि सरकार ने आरोपों को दबाने के बजाय तत्काल कार्रवाई की। ट्रस्ट की शिकायत पर एसआईटी बनी, गिरफ्तारियां हुईं और जांच लगातार आगे बढ़ रही है। अयोध्या के भाजपा नेता विकास मिश्र कहते हैं, "मुख्यमंत्री ने बिना किसी दबाव के तुरंत एसआईटी

बनाई. इससे यह संदेश गया कि योगी सरकार किसी को बचाने वाली नहीं है। यदि कहीं गड़बड़ी हुई है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी"।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा की रणनीति यह दिखाने की है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। पार्टी इस पूरे विवाद को 'सिस्टम की सफाई' के रूप में पेश करना चाहती है ताकि मंदिर की पवित्रता और सरकार की विश्वसनीयता दोनों पर आंच कम से कम आए।

2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) सामाजिक समीकरण के सहारे बड़ी सफलता हासिल की थी। लेकिन पार्टी नेतृत्व समझता है कि विधानसभा चुनाव में केवल उसी रणनीति को दोहराना पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए राम मंदिर के चढ़ावे का विवाद उसके लिए नया राजनीतिक अवसर बनकर सामने आया है। अखिलेश यादव लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं।

उन्होंने इसे केवल भ्रष्टाचार नहीं बल्कि श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा मामला बताया है। प्रयागराज में युवाओं के बीच उन्होंने कहा था, "भाजपा के लिए नेशन फर्स्ट नहीं, डोनेशन फर्स्ट है"। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि इस मुद्दे को केवल मीडिया तक सीमित नहीं रखा जाएगा। पार्टी की सहयोगी इकाई बाबा साहेब अंबेडकर वाहिनी प्रदेशभर में पीडीए पंचायतें, प्रशिक्षण शिविर और जनसंवाद कार्यक्रम चला रही है. वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, आगरा, गाजियाबाद और बलिया में कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। वाहिनी के राष्ट्रीय महासचिव रामबाबू सुदर्शन कहते हैं, "जब मामला जनता की आस्था और जनता के पैसे का हो, तब निष्पक्ष और पारदर्शी जांच जरूरी है। हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों से चर्चा कर रहे हैं कि आस्था से जुड़े मामलों में जवाबदेही क्यों जरूरी है।"

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि अखिलेश यादव इस मुद्दे के जरिए अपने पारंपरिक वोट बैंक से आगे बढ़कर शहरी मध्यवर्ग और सवर्ण मतदाताओं तक भी पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल के महीनों में ब्राह्मण सम्मेलनों का आयोजन, सैफई में केदारनाथ की तर्ज पर केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण और स्वयं राम मंदिर जाने की घोषणा इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। भाजपा के लिए इस विवाद की राजनीतिक संवेदनशीलता का एक बड़ा कारण 2024 का लोकसभा चुनाव भी है। राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा के केवल चार महीने बाद फैजाबाद लोकसभा सीट पर भाजपा की हार ने पूरे राजनीतिक परिदृश्य को चौंका दिया था। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने भाजपा के लल्लू सिंह को पराजित कर दिया। यह परिणाम इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि मंदिर निर्माण के बाद पहली बार जनता मतदान कर रही थी।

2022 के विधानसभा चुनाव में फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र की पांच विधानसभा सीटों में भाजपा तीन और समाजवादी पार्टी दो सीटें जीती थी, लेकिन 2024 में अयोध्या विधानसभा को छोड़कर बाकी चार विधानसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी को उल्लेखनीय बढ़त मिली। अयोध्या स्थित डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर आर. एस. वर्मा कहते हैं, "2024 में स्थानीय लोगों में जमीन अधिग्रहण, विस्थापन और शहर में बदले प्रबंधन को लेकर असंतोष था. समाजवादी पार्टी ने इसे सामाजिक समीकरण के साथ जोड़ दिया, लेकिन इस बार मामला स्थानीय नहीं है। अब सवाल देशभर के श्रद्धालुओं के दान से जुड़ा है इसलिए इसका असर कहीं व्यापक हो सकता है।"

हालांकि फरवरी 2025 के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज कर राजनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश की लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि यदि चढ़ावे के विवाद की जांच लंबी चलती है तो विपक्ष इसे लगातार चुनावी मुद्दा बनाए रखेगा। राजनीतिक विश्लेषक और चुनावी मामलों के जानकारों का मानना है कि भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह बहस को 'भ्रष्टाचार' से हटाकर फिर 'राम मंदिर और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' की ओर मोड़े जबकि विपक्ष चाहता है कि चर्चा केवल पारदर्शिता और जवाबदेही पर केंद्रित रहे।

भाजपा इस विवाद को केवल सफाई देकर समाप्त नहीं करना चाहती। पार्टी इसे वैचारिक स्तर पर जवाब देने की रणनीति पर भी काम कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस की रैली में अखिलेश यादव को श्रीकृष्ण जन्मभूमि आंदोलन का समर्थन करने की चुनौती दी। उनका संदेश स्पष्ट था कि विपक्ष यदि स्वयं को धार्मिक बताता है तो उसे मथुरा और काशी जैसे मुद्दों पर भी अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए.। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह कहते हैं, "जिन लोगों ने कारसेवकों पर गोलियां चलवाईं, उन्हें राम मंदिर पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जनता समाजवादी पार्टी के शासनकाल का भ्रष्टाचार और अपराध भूली नहीं है।" यानी भाजपा बहस को फिर 'हिंदुत्व बनाम विरोधी' की वैचारिक लड़ाई में ले जाना चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी इसे 'दान, पारदर्शिता और जवाबदेही' तक सीमित रखना चाहती है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यही 2027 के चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण नैरेटिव बन सकता है। यदि जांच शीघ्र पूरी होकर दोषियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई होती है, तो भाजपा इसे अपनी भ्रष्टाचार विरोधी नीति की सफलता के रूप में पेश करेगी। लेकिन यदि विवाद लंबा खिंचता है या जांच को लेकर सवाल उठते हैं, तो विपक्ष इसे आस्था और प्रशासनिक जवाबदेही के बड़े मुद्दे में बदलने का प्रयास करेगा। एक वरिष्ठ संघ पदाधिकारी, जिन्होंने नाम प्रकाशित न करने का आग्रह किया, कहते हैं, "राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। इसलिए प्रबंधन पर उठे किसी भी सवाल का जवाब पूरी पारदर्शिता से देना जरूरी है। जितनी जल्दी स्थिति स्पष्ट होगी, उतना ही अच्छा रहेगा। ■

न्यास का वेटिकन न्याय

मजनूं को बुरा कहती है लैला मेरे आगे...

अनिल तिवारी

बीते 12 दिसंबर 2021 को नागपुर की एक सभा में विश्व हिंदू परिषद के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ रविंद्र नारायण सिंह ने कहा था कि उनका और उनके मातृ संगठन का इरादा अयोध्या धाम को 'वैटिकन सिटी' की तर्ज पर विकसित करने का हैं। हालांकि तब तमाम संवेदनशील विशुद्ध भारतीयों को उनकी यह घोषणा नागवार गुजरी थी, लेकिन सरकारी भय के कारण किसी सनातनी ने 'चूं' तक नहीं किया था। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज करते हुए इसे भारतीय परंपरा के विपरीत माना लेकिन वे भी सत्ता का रंग ढंग देख जल्दी ही खोल के भीतर समा गए। अब मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले पर भाजपा की डबल इंजन सरकार ने जिस तरह सारा दारोमदार ट्रस्ट पर डाल किनारा कर लिया और ट्रस्ट ने अब तक जो कुछ भी किया उससे तो यही लग रहा है कि अयोध्या को वेटिकन बनाने का जो ब्लूप्रिंट विहिंप ने पेश किया था उसे अमली जामा पहनाया जाने लगा है।

पिछले एक महीने से देश दुनिया में शोर है कि अयोध्या मंदिर में चढ़ावा की चोरी हो रही है। चोरी का आरोप श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारियों चंपत बंसल, अनिल मिश्र और गोपाल राव सहित अन्य कर्मचारियों पर है। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तमाम लोग आरोपी चंपत बंसल को पाक साफ बताते हुए क्लीन चीट दे रहे हैं।

भारत में कानून का राज है।भारतीय न्याय संहिता में चोरी, डकैती,आर्थिक हेरा-फेरी, जुर्म है तथा इसकी

Kalrav July 2026_Kalrav 8/8/2026 11:46 AM Page 19

जांच कर दोषी को सजा देने के स्थापित नियम प्रावधान है, जो भारत संघ के सभी राज्यों में समान रूप से लागू है।

लेकिन इस सनसनीखेज मामले में सारी कानूनी कार्यवाही अत्यंत अलग ढंग से की जा रही है। बताते हैं कि ट्रस्ट के जिम्मेदार पदाधिकारी को चोरी का संज्ञान 5 जून को हो गया था। अगले दिन ट्रस्ट के महासचिव अनधिकृत रूप से पुलिस को साथ लेकर स्वयं ही कुछ आरोपियों के घर पर छापा मारने पहुंचे और 80 लाख रुपए बरामद किए जाने की बात सामने आई। प्रचलित कानून कहता है कि पुलिस की मौजूदगी में में हुई तलाशी और माल की बरामदगी के साथ ही आरोपियों के खिलाफ थाने में प्राथमिक की दर्ज कर बरामद रुपए को सरकारी माल-खाने में जमा करना चाहिए था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अलबत्ता 7 जून को ट्रस्ट के महासचिव बंसल ने मीडिया को बयान जारी कर कहा कि कोई उल्लेखनीय मामला प्रकाश में नहीं आया है, ट्रस्ट के ऑडिट का काम बदस्तूर चल रहा है।

चंपत बंसल के इस बयान के बाद चढ़ावा चोरी के खबर की आग पूरे देश दुनिया में फैलने लगी। विपक्षी दलों के साथ-साथ राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े वरिष्ठ नेताओं ने भी उंगली उठाना शुरू कर दिया। बजरंग दल के अध्यक्ष विनय कटियार, संतोष दुबे आदि के साथ-साथ विपक्षी दलों ने भी मंदिर से बड़ी लूट की आशंका जाहिर की। भारत सरकार की ओर से नामित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निर्माण समिति के अध्यक्ष पूर्व नौकरशाह नृपेंद्र मिश्र ने यह कहकर कि मंदिर में चोरी नहीं बल्कि डकैती हुई है उस आग में घी डालने का काम किया।

यत्र-तत्र-सर्वत्र ट्रस्ट की छिछालेदर होने लगी। बताते हैं कि जगहंसाई से बचने के लिए ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार से जांच का अनुरोध किया, फिर मामले की जद में आ रहे हाई प्रोफाइल लोगों को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बिना प्राथमिकी के आनन-फानन में एक विशेष जांच दल की घोषणा की। जांच दल मुस्तैदी के साथ छानबीन कर अपनी अंतरिम रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। सूत्रों के मुताबिक अंतरिम रिपोर्ट लीक होकर ट्रस्ट के पदाधिकारी तक पहुंच गई। फिर ट्रस्ट के सदस्य की ओर से आठ आरोपियों के खिलाफ प्राथमिक की दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर उन सब की गिरफ्तारी हुई।

चूंकि सभी अपराधी मोटे तौर पर चंपत बंसल, अनिल मिश्र और गोपाल राव के भरोसेमंद लोग थे इसलिए इनके

कुछ सवाल

1. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का गठन उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर भारत सरकार द्वारा किया गया है? क्या सरकार ने न्यास गठन में उचित प्रतिनिधित्व, समता का अवसर जैसे संविधान सम्मत उद्देश्यों का पालन किया गया है?

   यदि न्यास का गठन धार्मिक आधार पर हुआ है तो क्या हिंदू धर्म के चारों शंकराचार्य,सभी प्रमुख अखाड़ों, संप्रदायों का प्रतिनिधित्व या उनकी सहमति है?

2. नए और भव्य राम मंदिर का निर्माण सरकार द्वारा अधिग्रहित 67.7 एकड़ जमीन पर किया गया है जिसका पैसा सरकारी खजाने से जमा किया गया है। क्या भारत की जनता सूचना के अधिकार के तहत जानकारी हासिल कर सकेगी?

3. भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ ही जमीन घोटाले के आरोप लगने लगे थे। इसे लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक जांच दल गठित किया था, उसकी रिपोर्ट कब सार्वजनिक होगी?

4. आरोप है कि एक जमीन 2 करोड़ रुपए के मूल्य पर बेची गई, विक्रय पत्र पर जिन दो गवाहों के हस्ताक्षर हैं, वहीं जमीन 10 मिनट के बाद जब राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 18 करोड़ में बेची गई उस पर भी उन्हीं दोनों गवाहों के हस्ताक्षर हैं। क्या बिना दाखिल खारिज के एक जमीन 10 मिनट के अंदर दूसरे को बेची जा सकती है? क्या ऐसी कोई दूसरी नजीर देश के राजस्व विभाग में कहीं मौजूद है?

5. हालिया घटना के प्रकाश में आने के बाद न्यास प्राथमिकी दर्ज कराने की बजाय खुद ही पुलिस लेकर छापामारी करने पहुंच गया। जो पुलिस दल छापामारी करने गया था उनकी तैनाती कहां थी, बिना किसी प्राथमिक के वे किसके आदेश पर गए थे और गए थे तो क्या उनकी रवानगी पुलिस डायरी में प्रस्तुत है? उनकी आमद कब हुई इसका कोई उल्लेख है?

6. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित जांच दल की रिपोर्ट कैसे लीक हुई, लीक रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट ने प्राथमिकी दर्ज कराई। जांच दल ने यह प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज कराई?

7. जांच की अंतिम रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है। बोर्ड की बैठक में नौ पन्नों की अंतरिम रिपोर्ट आधिकारिक रूप से कैसे दिखाई बताई गई?

8. न्यास के कोषाध्यक्ष ने बार-बार अपनी व्यस्तता का हवाला दिया है। उनके पास मंदिर के हिसाब किताब का समय नहीं है। वह अपना काम आउटसोर्सिंग के जरिए करते रहे हैं। इतने बड़े प्रकल्प के लिए आखिर उन्हीं को क्यों रखा गया है जबकि उनके पास कोई वित्तीय विशेषज्ञता भी नहीं है?

विरुद्ध जनाक्रोश आगे भी तारी रहा। इन तीनों को न्यास से हटाए जाने की मांग तेज होने लगी। विश्व हिंदू परिषद ने पहले एसआईटी जांच का हवाला दिया और कहा कि इस बारे में कोई भी निर्णय ट्रस्ट की बैठक में लिया जाएगा। जांच दल की फाइनल रिपोर्ट आने के पहले ही ट्रस्ट की बैठक हुई। बैठक में चंपत बंसल और अनिल मिश्र के इस्तीफे पर मुहर लगी, आमंत्रित सदस्य गोपाल राव को बाहर कर दिया गया। कृष्ण मोहन को ट्रस्ट का नया महासचिव चुने जाने तक के लिए कार्यकारी महासचिव घोषित किया गया। भविष्य में देखरेख के लिए एक सीईओ नियुक्त किए जाने की भी अनुशंसा बैठक में हुई।

कुल मिलाकर ट्रस्ट की बैठक में हू ब हू वही सब हुआ जिसकी चर्चा बहुत पहले से मीडिया और आम लोगों के बीच सरेआम थी। मसलन ट्रस्ट द्वारा चंपत बंसल की महानता की भूरि भूरि प्रशंसा की गई। चोरी में शामिल बड़े किरदारों को बाहर लाने की वजाय पकड़े गए छोटे अपराधियों के मत्थे मढकर पूरे प्रकरण को रफा दफा करने की कवायद की गई। चढ़ावा चोरी के मामले में ट्रस्ट पर उंगली उठी। ट्रस्ट ने खुद ही छापामारी कर माल बरामद किया। ट्रस्ट ने एसआईटी जांच की मांग की। ट्रस्ट ने जांच रिपोर्ट लीक की और उसी के आधार पर ट्रस्ट ने ही प्राथमिक की दर्ज कराई। ट्रस्ट ने बैठक बुलाई। ट्रस्ट ने दो ट्रस्टियों का इस्तीफा स्वीकार किया। और सबसे अंत में ट्रस्ट ने मुख्य आरोपी चंपत बंसल को कर्मठ, निष्कलंक, पाक साफ बताते हुए चढ़ावा चोरी पुराण का पहला अध्याय समाप्त किया। अथ द्वितीयो अध्याय का पन्ना 22 जुलाई को पलटने का निर्णय हुआ है।

बैठक के बाद न्यास के कोषाध्यक्ष ने सीमित प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निर्णय की जानकारी दी और विशेष रूप से हिदायत दी की चंपत बंसल पर जो भी आरोप लगे हैं सब मनगढ़ंत हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बंसल जी से किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा। न्यास के अधिकांश सदस्य उनका इस्तीफा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन न्यास के वरिष्ठ सदस्य पराशरन की परामर्श के बाद भारी मन से न्यास में उनका इस्तीफा स्वीकार किया है। प्रचलित जांच की अंतिम रिपोर्ट आने के पहले ही निर्णायक अंदाज में उन्होंने क्लीन चीट दे दी। बिल्कुल वेटिकन की तरह अयोध्या के लिए बनाए जा रहे नए-नए कायदा कानून के अंदाज में।

इस तरह के ढेर सारे सवाल उठे हैं। विश्व हिंदू परिषद के कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिष्ठा पर भी बट्टा लगा है।विपक्षी पार्टियां केंद्र और राज्य की सरकार को दोषी ठहराते हुए जवाब मांग रही हैं। आमजन चढ़ावा चोरी की घटना से स्तब्ध है। अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से लोग तरह-तरह की चर्चा कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी नामचीन लोग निकल कर आए हैं जो अपने चंदे चढ़ावे का हिसाब मांग रहे हैं। एक कोई पूर्व वरिष्ठ नौकरशाह है जो अपने खानदान की पूरी कमाई से रामचरितमानस बनवाकर चढ़ा आए थे। अब उसे खोज रहे हैं। ट्रस्ट ने जब प्रदर्शित किया तब से चुप हैं।

भारत में धर्म की अद्भुत महता है। हमारे यहां दान का अलग प्रावधान है और कानूनी विधान भी है। व्यवहार और कानून दोनों की नजर में एक बार जो चीज दान कर दी गई, फिर घूम कर उसकी तहकीकात नहीं की जाती। हमारे देश में जितने भी धार्मिक मंदिर बने हैं उनमें राजे राजवाड़े से लेकर आम जनता के दान शामिल हैं। आज तक कभी किसी ने अपने दिए हुए दान की तहकीकात नहीं की। भारत की आम जनता श्रद्धा से अयोध्या जाती है तथा अपनी शक्ति और सामर्थ्य के हिसाब से जो कुछ भी बन पड़ता है, अपने राघव राजा राम की सेवा में अर्पित करती है। भारत की आम जनता को दान का हिसाब नहीं चाहिए। भारत का लोक मन जो दे दिया सो दे दिया वाला है।

लेकिन मंदिर में जिस डकैती का संकेत मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष ने किया है वह लज्जा जनक है। कलंक है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा को तार-तार करने वाला है। अयोध्या को पोप नगरी (वेटिकन सिटी) की तर्ज पर विकसित करने वालों का पाप पकड़ गया है, उन्हें वेटिकन की तरह नए कानून से डील करने की वजाय भारतीय न्याय संहिता मे स्थापित कानून के हिसाब से सजा स्वीकार कर प्रायश्चित करना चाहिए। घट घट व्यापी राम सब देख रहे हैं। राम के दास बाबा तुलसी ने तो सैकड़ो साल पहले ही देख लिया था और रामचरितमानस के बालकांड में ही ऐसे लोगों के लिए लिख दिया था,

वंचक भगत कहाइ राम के। किंकर कंचन कोह काम के।। ■

Kalrav July 2026_Kalrav 8/8/2026 11:46 AM Page 21

राम के चिरई-राम के खेत, खाऽल चिरई भर-भर पेट

संजय जयहिंद

राम नाम की लूट के लिए भारी-भरकम बजट से संवारे सजाए जा रहे अयोध्या मंदिर में राम के नाम पर लूट किए जाने की दुखद खबरें इन दिनों सुर्खियों में है। उत्तर प्रदेश सरकार मामले की बिना कोई प्राथमिकी दर्ज किये लुटेरों को धर-दबोचने के लिए विशेष जांच दस्ता (एसआईटी) का गठन किया है। मुख्यमंत्री ने जब से यह ऐलान किया है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, जांच दल धुएं के सहारे अपराध की आग तक पहुंचने की सरकारी नौटंकी कर रहा है। क्योंकि जांच दल को पता है कि उसे जिस आग को पकड़ने का जिम्मा दिया गया है, उस पर हाथ रखते ही उसके खुद के झुलसने की संभावना बराबर है। चूंकि मामला बड़ा है, इसलिए इसमें बड़े-बड़ों की संलिप्तता की आशंका है। वर्षों से मंदिर के चढ़ावे की देखरेख मे लगे चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्र आदि पदाधिकारियों की जड़े बहुत दूर-दूर तक पसरी हुई हैं। चंपत राय सरीखे पदाधिकारीगण जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पवित्र संस्कारों से संस्कारित हैं, उन्हें चढ़ावा चोरी जैसे अपवित्र आचरण के लिए दोषी ठहराना न सिर्फ कठिन है बल्कि आज की तारीख में राष्ट्रद्रोह जैसा भी हो सकता है। इसीलिए हर दिन मामले को लेकर नए-नए नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं।

मामले में जो कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है वह यह कि एसआईटी संदिग्ध लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है। मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारी को अयोध्या न छोड़ने की हिदायत दी गई है। ड्राइवर टीनू यादव के ठिकानों सहित कई स्थान से भारी रकम की बरामदगी उजागर हुई है। चोरी की घटना के उजागर होने के बाद से राम मंदिर में आने वालों की संख्या में कमी आई है वही चढ़ावे की रकम में 72% की गिरावट दर्ज की गई है। पहले जहां प्रतिदिन 18 से लेकर 25 लख रुपए तक चढ़ावे में आता था अब वह घटकर 5 लाख के नीचे आ गया है।

देश के विपक्षी दल लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाते हुए स्वच्छ और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार के संतुलनकर 'सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे' के लिए अलग-अलग ढंग से कवायद कर रहे हैं। सरकारी पक्ष की और से यह भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों को अवसर नहीं मिला वो षड्यंत्र कर रहे हैं।

आरंभिक चरणों में अयोध्या राम मंदिर आंदोलन के हीरो रहे बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय कटियार चोरी का आरोप लगा रहे हैं। मंदिर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले पूर्व सांसद बृजभूषण शरण

Kalrav July 2026_Kalrav 8/8/2026 11:46 AM Page 22

सिंह अपने मुंह पर ताला डाले हुए हैं। उनका कहना है कि अगर वह मुंह खोलेंगे तो बड़े लोग उनका बड़ा नुकसान कर सकते हैं। अयोध्या के स्थाई साधु संत करोड़ों की बंदर-बांट से हतप्रभ हैं। अपनी गाढ़ी कमाई का कुछ हिस्सा अपने आराध्य श्री राम को देने वाली भोली भाली जनता ठगी सी है, और हर जम्हाई के साथ ऊपर आसमान की ओर देखकर पूछ रही है कि 'हे भगवान, आपकी अयोध्या में, मंदिर के अंतःपुर में यह क्या हो रहा है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अयोध्या की मर्यादा को तार तार करने वाले आखिर कौन हैं?

भारत की पहचान केवल उसकी भौगोलिक सीमाओं,भाषाई विविधता या सांस्कृतिक विरासत से नहीं होती,बल्कि उसकी गहरी धार्मिक चेतना और आस्था से भी होती है। यहां मंदिर केवल पूजा-अर्चना के स्थल नहीं हैं,बल्कि समाज की भावनाओं,विश्वासों और सांस्कृतिक निरंतरता के केंद्र भी हैं। करोड़ों लोग अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए मंदिरों में दान,दक्षिणा,चढ़ावा और सेवा अर्पित करते हैं।यह दान केवल आर्थिक लेन-देन नहीं होता,बल्कि भक्त और भगवान के बीच विश्वास का एक आध्यात्मिक सेतु होता है। यही कारण है कि जब किसी धार्मिक संस्था,ट्रस्ट या मंदिर के प्रबंधन को लेकर प्रश्न उठते हैं,तब मामला केवल प्रशासनिक या आर्थिक नहीं रह जाता,बल्कि सीधे- सीधे आस्था,विश्वास और जवाबदेही से जुड़ जाता है।

भारतीय लोकमन एक कहावत है "राम-राम जपना,चढ़ावे का माल अपना।" यह कहावत किसी धर्म, देवता या आस्था का उपहास नहीं करती,बल्कि उन प्रवृत्तियों पर व्यंग्य करती है जो धर्म और नैतिकता की बात तो करती हैं, किंतु व्यवहार में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व से दूर दिखाई देती हैं। आज जब अयोध्या राम मंदिर से करोड़ों श्रद्धालुओं का चढ़ावा चोरी की बात निकली है,तब यह कहावत कुछ असहज किंतु आवश्यक प्रश्न भी खड़े करती है।

अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था।यह स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े जन आंदोलनों में से एक था। 500 वर्षों तक चले संघर्ष,सामाजिक विमर्श, राजनीतिक बहसों और न्यायिक प्रक्रिया के बाद जब मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ, तब देश के कोने-कोने से लोगों ने इसे अपनी व्यक्तिगत आस्था का विषय मानकर सहयोग दिया। गाँवों से लेकर महानगरों तक,भारत से लेकर विदेशों तक,करोड़ों लोगों ने आर्थिक और भावनात्मक रूप से इस अभियान में भागीदारी की। किसी ने एक रुपया दिया,किसी ने लाखों रुपये का दान किया।अनेक श्रद्धालुओं ने सोना,चाँदी,हीरे,मोती और बहुमूल्य रत्न अर्पित किए। कई परिवारों ने पीढ़ियों से संभालकर रखे गए आभूषण रामलला को समर्पित कर दिए। महिलाओं ने अपने विवाह के गहने तक दान कर दिए। बुजुर्गों ने अपनी जीवनभर की बचत का हिस्सा भगवान के चरणों में अर्पित किया। यह केवल आर्थिक योगदान नहीं था,बल्कि श्रद्धा,समर्पण और विश्वास की अभिव्यक्ति थी।

मंदिर आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यही रही कि इसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी दिखाई दी। गरीब,मध्यमवर्गीय और संपन्न

Kalrav July 2026_Kalrav 8/8/2026 11:46 AM Page 23

सभी ने अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दिया।यही कारण है कि मंदिर से जुड़ा प्रत्येक संसाधन केवल संपत्ति नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के विश्वास का प्रतीक है। लोगों ने यह मानकर दान दिया कि उनका योगदान भगवान राम के भव्य मंदिर और उससे जुड़े धार्मिक-सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति में लगेगा। भारतीय संस्कृति में दान और चढ़ावे की परंपरा अत्यंत प्राचीन है।मंदिरों को सदियों से समाज ने केवल पूजा स्थलों के रूप में नहीं,बल्कि लोककल्याण के केंद्र के रूप में भी देखा है।इतिहास गवाह है कि अनेक मंदिरों ने शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक सहायता और सांस्कृतिक संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्रद्धालु जब मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं,तब वे केवल धन नहीं देते, बल्कि संस्था के प्रति अपना विश्वास भी सौंपते हैं।यही विश्वास किसी भी धार्मिक संस्था की सबसे बड़ी पूँजी होता है।यही कारण है कि जब चढ़ावे में प्राप्त बहुमूल्य वस्तुओं, आभूषणों और रत्नों के संबंध में किसी प्रकार की अनियमितता,चोरी अथवा अभिलेखीय विसंगतियों की चर्चा सामने आती है,तो समाज में स्वाभाविक रूप से चिंता उत्पन्न होती है।

जांच में पता चला है कि चढ़ावे में प्राप्त मूल्यवान वस्तुओं के रिकॉर्ड और वास्तविक स्थिति को लेकर पारदर्शिता अपेक्षित स्तर की नहीं है। जांच एजेंसियों की भूमिका को लेकर भी प्रश्न उठने लगे। यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आरोप,जांच और न्यायिक निष्कर्ष तीन अलग-अलग चरण होते हैं। केवल आरोपों के आधार पर किसी संस्था या व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। साथ ही जब मामला करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हो,तब उठ रहे प्रश्नों को केवल अफवाह कहकर खारिज कर देना भी उचित नहीं माना जा सकता। जन विश्वास बनाए रखने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों अनिवार्य हैं।

राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं,बल्कि राष्ट्रीय भावना, सांस्कृतिक चेतना और सभ्यतागत स्मृति का प्रतीक है।इसीलिए उससे जुड़े प्रत्येक निर्णय,प्रत्येक व्यवस्था और प्रत्येक संसाधन पर समाज की निगाह है। श्रद्धालु यह जानना चाहते हैं कि उनके द्वारा समर्पित धन और बहुमूल्य वस्तुओं का संरक्षण किस प्रकार किया जा रहा है,उनका लेखा-जोखा कैसे रखा जा रहा है,क्या स्वतंत्र ऑडिट की व्यवस्था है,क्या समय-समय पर सार्वजनिक रिपोर्ट जारी की जाती है तथा क्या चढ़ावे का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित और सत्यापित रूप में उपलब्ध है। ये प्रश्न किसी धर्म, व्यक्ति या संस्था विशेष के विरोध में नहीं हैं।वास्तव में ये प्रश्न उन करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास की रक्षा से जुड़े हैं जिन्होंने राम मंदिर निर्माण को अपना व्यक्तिगत और सांस्कृतिक दायित्व मानकर सहयोग दिया था।लोकतांत्रिक समाज में पारदर्शिता को अविश्वास का प्रतीक नहीं,बल्कि विश्वास को और अधिक मजबूत करने का माध्यम माना जाता है।यहीं पर राम मंदिर निर्माण और उसके संचालन से जुड़ी प्रबंधन व्यवस्था तथा प्रबंधन समिति की भूमिका चर्चा के केंद्र में आ जाती है।किसी भी बड़े धार्मिक संस्थान की विश्वसनीयता केवल उसकी भव्यता से निर्धारित नहीं होती।उसके प्रशासनिक मानक,वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।यदि प्रबंधन व्यवस्था पारदर्शी,व्यवस्थित और उत्तरदायी दिखाई देती है, तो श्रद्धालुओं का विश्वास स्वतः बढ़ता है।यदि कहीं अस्पष्टता या सूचना का अभाव दिखाई देता है,तो प्रश्न उठना स्वाभाविक हो जाता है।

जब किसी संस्था को जनता का व्यापक समर्थन और संसाधन प्राप्त होते हैं,तब उसके साथ जवाबदेही भी जुड़ जाती है।श्रद्धालु यह अपेक्षा करते हैं कि मंदिर से जुड़े सभी आर्थिक और प्रशासनिक कार्य पूर्ण पारदर्शिता के साथ संचालित हों।यदि कहीं कोई शिकायत या संदेह उत्पन्न होता है, तो उसका समाधान तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर किया जाए। यही किसी भी प्रतिष्ठित संस्था की साख को मजबूत करने का सबसे प्रभावी तरीका है।भारत का संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था यह स्पष्ट करती है कि कोई भी संस्था कानून से ऊपर नहीं है।चाहे वह धार्मिक संस्था हो,सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक दल हो अथवा कोई बड़ी कॉरपोरेट इकाई -सभी के लिए कानून समान है। इसलिए यदि किसी प्रकार की शिकायत सामने आयी है,तो जांच एजेंसियों को न्याय और मर्यादा की रक्षा हर हाल में करनी चाहिए।

किसी संस्था के विरुद्ध जांच का उद्देश्य दोषी ठहराना नहीं,बल्कि सत्य तक पहुंचना होता है। यदि सब कुछ व्यवस्थित और पारदर्शी है, तो जांच संस्था की विश्वसनीयता को और मजबूत कर सकती है।यदि कहीं कोई त्रुटि या अनियमितता है, तो उसका सामने आना भी आवश्यक है।यही कानून के शासन का मूल आधार है।दुर्भाग्य से समाज में अक्सर दो चरम स्थितियां देखने को मिलती हैं।एक वर्ग बिना किसी निष्कर्ष के ही आरोपों को सत्य मान लेता है।दूसरा वर्ग केवल भावनाओं के आधार पर हर प्रश्न को साजिश घोषित कर देता है।दोनों ही दृष्टिकोण स्वस्थ लोकतांत्रिक विमर्श के लिए उचित नहीं हैं।सत्य तक पहुंचने का मार्ग तथ्यों,प्रमाणों और निष्पक्ष जांच से होकर गुजरता है।

भगवान श्रीराम भारतीय संस्कृति में मर्यादा,न्याय और सत्य के सर्वोच्च प्रतीक माने जाते हैं।रामराज्य की अवधारणा केवल धार्मिक भावना नहीं,बल्कि सुशासन का आदर्श भी है।रामराज्य का अर्थ ऐसी व्यवस्था से है जहां शासन पारदर्शी हो,न्याय निष्पक्ष हो और जनता का विश्वास सर्वोपरि हो। वहां राजा स्वयं भी नैतिक जवाबदेही से मुक्त नहीं था। यही कारण है कि भगवान राम आज भी केवल धार्मिक श्रद्धा के विषय नहीं,बल्कि आदर्श शासन और नैतिक नेतृत्व के प्रतीक माने जाते हैं।यदि राम के नाम पर निर्मित किसी संस्था या व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग उठती है,तो उसे विरोध के रूप में नहीं,बल्कि रामराज्य के आदर्शों के अनुरूप सुधार की प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए।आखिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जीवन स्वयं सत्य,मर्यादा और उत्तरदायित्व का संदेश देता है। ■

Kalrav July 2026_Kalrav 8/8/2026 11:46 AM Page 24

समग्र हिंदुत्व की राह पर भाजपा

धीरेंद्र जयहिंद

वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश में सभी राजनैतिक दलों ने अपनी चुनावी तैयारियों और मुद्दों को अंतिम रूप देना प्रारंभ कर दिया है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बहुप्रतीक्षित कार्यकारिणी भी घोषित कर दी है। माना जा रहा है कि भाजपा की यह टीम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व केंद्रीय नेतृत्व की पसंद से चुनी गई है किन्तु इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी महती भूमिका है।

भाजपा ने अपनी नई टीम में सामाजिक सन्तुलन साधने के साथ ही सपा के पीडीए व बसपा के ब्राह्मण कार्ड को रोकने का प्रबंध किया है। अब चुनाव केवल सामाजिक समीकरण के बल पर ही नहीं जीते जाते इसलिए भाजपा ने अपनी टीम की संरचना से यह भी स्पष्ट किया है कि वह चुनावी दंगल बूथ स्तर पर आकर ही लड़ेगी। भाजपा अब अपने बूथ प्रबंधन को सशक्त करने के लिए काम करेगी जिसके लिए प्रदेश की टीम को एकदम युवा व कर्मठ चेहरे दिए गए हैं। भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी में प्रवक्ताओं की टीम भी घोषित कर दी गई है और सोशल मीडिया प्रमुख की भी नियुक्ति की गई है क्योंकि अब प्रमुख राजनैतिक नैरेटिव युद्ध पारंपरिक और सोशल मीडिया दोनों पर लड़ा जाता है। चुनावी जंग जीतने में मीडिया व सोशल मीडिया भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पश्चिम बंगाल चुनावों में नैरेटिव युद्ध ने भाजपा की विजय में बड़ी भूमिका निभाई थी।

प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की नई टीम में सपा

Kalrav July 2026_Kalrav 8/8/2026 11:46 AM Page 25

के पीडीए की धार कुंद करने का प्रयास किया गया है। राज्य में भाजपा का संगठन 6 क्षेत्रों में विभाजित है। इनमें पश्चिम नवाब सिंह नागर को, ब्रज क्षेत्र में पूरन लाल लोधी तथा कानपुर क्षेत्र में राम किशोर साहू अध्यक्ष बने हैं। काशी क्षेत्र के अध्यक्ष अशोक चौरसिया बनाए गए हैं। अवध के क्षेत्रीय अध्यक्ष अवधेश द्विवेदी बने हैं। गोरखपुर क्षेत्र की कमान विनोद राय को मिली है जो भूमिहार हैं। प्रदेश में 19 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और इनमें भी ओबीसी वर्ग को प्राथमिकता दी गई है। 8 महामंत्रियों की सूची मे भी 4 ओबीसी वर्ग के हैं।

प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी के चयन में सामाजिक संतुलन के साथ-साथ क्षेत्रीय संतुलन साधने का प्रयास भी किया गया है। सपा छोड़कर भापजा मे शामिल हुई पूजा पाल को प्रयागराज में जिम्मेदार दी गई है। एक समय प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद का आतंक था और उस पर पूजा पाल के पति राजू पाल की हत्या का आरोप था। भाजपा ने अपनी कार्यकारिणी के माध्यम से दलित गैर-जाटव समुदाय से पासी और कोरी समाज को भी साधने का प्रयास किया है। भाजपा ने कुशवाहा, मौर्य और सैनी समुदाय से तीन नेताओं को उपाध्यक्ष बनाया है जाट, कुर्मी, यादव और पाल समाज से भी उपाध्यक्ष बनाया गया। भाजपा की कार्यकारिणी से प्रतीत हो रहा है कि भाजपा के तरकश में अभी कई तीर छिपे हैं। यह बात तो तय हो गई है कि अब भाजपा समग्र हिंदुत्व की राजनीति करने जा रही है। भाजपा व संघ द्वारा अब प्रदेश में बंगाल की ही तरह 94 प्रतिशत हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने का प्रयास किया जाएगा।

भाजपा कार्यकारिणी की सूची आते ही सपा, बसपा व कांग्रेस की राजनीतिक हलचलें भी तेज हो गई है। यह चर्चा भी सुनी जा रही है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के चुनाव वर्ष 2026 के अक्टूबर- नवंबर में भी करवा सकता है क्योंकि आगे जनगणना का वृहद अभियान चलना है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल तथा असम सहित कई राज्यों के निकाय चुनावों में लगातार मिल रही सफलता से उत्साहित है और अपनी विजय का संवेग बनाए रखने के लिए के लिए विपक्ष को तैयारी के लिए समय नहीं देना चाहती। ■

Kalrav July 2026_Kalrav 8/8/2026 11:46 AM Page 26

साधो, देखो जग बौराना!

कितनी सुखद अनुभूति होती है , जब रात्रि के दूसरे पहर अपने घर की छत पर बैठकर श्वेत चांदनी की चादर ओढ़े चंद्रमा को देखते हैं या फिर टिमटिमाते सितारों के समूह में कभी खरगोश तो कभी रथ की आकृति ढूंढने की कोशिश करते हैं। ह्रदय कितना प्रफुल्लित होता है जब सुबह तड़के आप उषा की लालिमा देखते हुए शीतल हवाओं को महसूस करते हैं, पक्षियों का मधुर कलरव सुनते हैं। किंतु प्रश्न यह है कि आखिर हममें से कितने लोग ऐसे हैं जो इन अनुभूतियों से परिचित हैं? आधुनिकता की इस चकाचौंध में हमने अपनी आंखें इस तरह मूंद ली हैं कि हमें अपने सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता। हमारा जीवन चक्र 'मैं', 'मेरा' और 'मुझे' के वृत्त में सिमट गया है। हमें अपने आसपास के लोग तो छोड़िए अपने परिवेश तथा पर्यावरण से भी कोई मतलब नहीं है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इस सामाजिक प्राणी को पशु से मनुष्य बनाता है उसका विवेक किंतु शायद हम वैभव, संपन्नता तथा ऊंची इमारतों, बड़े-बड़े कल कारखानों, ऊंचे पद-प्रतिष्ठाके घेर जाल में फंसकर अपना विवेक खो चुके हैं। नामचीन कवि 'पाश' ने लिखा है "सबसे खतरनाक होता है व्यक्ति का मुर्दा बन जाना, घर से काम पर जाना और काम से लौट कर घर आना"। एक मशीनी दिनचर्या का पालन करते हुए स्वयं को 'स्वः' तक ही समेट लेंगे तो हमारे विचारों को और हमारी दिनचर्या को एक नया आयाम भला कैसे मिलेगा? वर्तमान परिपेक्ष्य में यदि देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और दवाई जैसी वस्तुएं आती हैं किंतु हमने इन आवश्यकताओं के अर्थ को अपनी अभिलाषानुसार ढाल कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर दिया है। उदाहरण के तौर पर जब भी हम मकान शब्द के बारे में सोचते हैं तो खुद ब खुद एक 27 मंजिला इमारत एन्टिलिया का चित्र हमारे मस्तिष्क में खिंच जाता है, कपड़े की बात हो तो, ज़ारा, पीटर इंग्लैंड, एच एन एम, जैसी कंपनियों के नाम हमें याद आते हैं। वास्तव में हम जाने अनजाने में आधुनिकता के अदृश्य जाल का, पागलपन की स्पर्धा

गौरी तिवारी

Kalrav July 2026_Kalrav 8/8/2026 11:46 AM Page 27

का शिकार हो गए हैं और हमने जीवन का एक ही लक्ष्य बना लिया है कि इस अंधीदौड़ में सामने वाले व्यक्ति से आगे जाना है। जिसके चलते हम अपने जीवन को असल मायने में खुलकर नहीं जी रहे, जिंदगी के कई रंगों से अपरिचित हैं तथा अनमोल अनुभूतियों को मामूली समझ कर अनदेखा कर रहे हैं। यह भूल रहे हैं कि जो अनुभूतियां आपके लिए साधारण है वह किसी अन्य के लिए उसका स्वप्न हो सकती हैं।

वह अबोध बालक जिसके लिए संसार का अर्थ सिर्फ अंधेरा और रंग का अर्थ सिर्फ काला है, क्या वह कभी वसंत ऋतु में रंग-बिरंगे पुष्पों से लदे पेड़ के हरे पत्तों की लाल तथा हल्की पीले धारियों की खूबसूरती देख सकेगा? क्या वह संध्या की लालिमा या पूर्णिमा की चांदनी का अनुभव कर पाएगा? अक्सर मेट्रो और बस में सफर करते समय देखा जा सकता है कि किस प्रकार यात्रा कर रहे अधिकतर लोगों का ध्यान उनके मोबाइल फोन से नहीं हटता। उनकी आंखें मोबाइल फोन के स्क्रीन से इतर कुछ नहीं देखती, किसी ने कान में इयरबड्स लगाए हुए हैं तो किसी ने बड़े गर्व से ब्लूटूथ इयरफोन अपने गले में लटका रखा है जैसे की वह कोई एयर फोन ना हो अपितु बड़ी फैशनेबल वस्तु हो और कुछ महानुभाव ऐसे भी हैं जिनके पास यदि ईयर फोन ना हो तो वे अपने फोन की आवाज इतनी तेज रखते हैं कि अपने साथ-साथ दूसरों को भी सुनाते हैं कि वे क्या देख सुन रहे हैं। कई बार तो ऐसे लोग मनोरंजन का पात्र बन जाते हैं। कुछ तो इतना उन्मत होकर मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं कि उन्हें अपने आसपास के बारे में भी नहीं पता होता कि क्या हो रहा है।

एक बार दिल्ली मेट्रो में सफर करते हुए मैंने पहले डिब्बे की दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित सीटों पर बैठे एक परिवार जिसके सभी सदस्य दृष्टिहीन थे उनके माध्यम से जिंदगी जीने की कला देखी और कुछ-कुछ सीखने की भी कोशिश की। एक शत प्रतिशत दृष्टिहीन मां जिसके चारों ओर सिर्फ अंधकार है, उसके हृदय के एक कोने में भी हर पल उसके बच्चे को खोने का डर विद्यमान है, यदि थोड़ी देर के लिए भी उसके बच्चों की खिलखिलाहट, उनकी अनुगूंज उसके कानों तक न जाए तो उसका मन बेचैन हो जाता है। चाह कर भी अपने बच्चे को न देख पाने की पीड़ा मैंने एक मां के मुख पर देखी। दांपत्य जीवन में एक दूसरे के सुख-दुख में साथ देने वाले प्रेम को उन माता-पिता में देखा। मैंने महसूस किया कि प्रकृति के विभिन्न रंगों को देखने में असमर्थ उन बच्चों के माता पिता ने जीवन के कई रंग देख लिए शायद जिनसे हम में से कई लोग अपरिचित हैं। उन्होंने साबित किया कि जीवन में तमाम तरह के दुखों के बावजूद एक व्यक्ति का कोमल स्पर्श, उसका प्रेम से हाथ पकड़ना कैसे दूसरे व्यक्ति में साहस भर देता है, एक उम्मीद की लौ जगाता है कि यदि आपस में प्रेम हो तो हम साथ मिलकर सारे दुखों को पार कर सकते हैं।

रात के समय यदि घर की बिजली चली जाए या आंखमिचौली खेलते समय कोई हमारी आंखों पर काली पट्टी बांध दे और हमारे चारों ओर सिर्फ अंधकार ही अंधकार हो तो हम एक कदम भी नहीं बढ़ा पाते, हर क्षण एक अजीब सा डर रहता है और मन चाहता है कि जल्दी से कोई मोमबत्ती जला दे या फिर आंखों की पट्टी खोल दे ताकि यह अंधकार दूर हो भले ही अंधकार कुछ क्षण का ही क्यों ना हो। आप सोचिए जिनका जीवन ही अंधकार में हो उनके हृदय पर कैसा

Kalrav July 2026_Kalrav 8/8/2026 11:46 AM Page 28

वज्रपात होता होगा? पग पग पर जो कुछ न देख सकने के कारण लड़खड़ा जाए, उन्हें कितनी पीड़ा होती होगी? उनका जीवनयापन कैसे होता होगा? जिनकी जीविका का एकमात्र स्रोत दिहाड़ी मजदूरी है, बिना आंखों की रौशनी के वो काम कैसे करते होंगे? उनके परिवार का गुजारा कैसे होता होगा? जब एक मां एक नई कलि को जन्म देकर इस संसार में लाती होगी तब सिर्फ एक बार ही सही किंतु अपने बच्चों की मधुर मुस्कान उसके मासूम चेहरे को देखने की तृष्णा क्या कभी मिट सकेगी? न देख पाने की कसक उसे जरूर सालती होगी।

लेकिन ईश्वर ने जिन्हें आंखों की रोशनी जैसी अमूल्य भेंट दी है, उन्हें इसकी परवाह कदाचित नहीं है। वे प्रकृति की इस रमणीयता को अनदेखा करते हैं, साधारण समझते हैं, वे जीवन को एक बेहतर ढंग से जीने से चूक जाते हैं और जीवन के अनेक रंगों से अपरिचित रह जाते हैं।

आमतौर पर कुछ लोगों की आदत होती है प्लेट में जरूरत से ज्यादा भोजन लेकर फेंक देने की, महंगे होटलों में खाना खाने की, छोटी दुकान वालों के खाने को 'अनहाइजीनिक' बोलकर वही चीज किसी ऐसे बड़े होटल में खाने की जहां उन्हें खुद नहीं पता कि भोजन की सामग्री कितने समय से फ्रीजर में रखी गई है। लेकिन फुटपाथ पर सो रहे उन बेघर लोगों के लिए ऐसे लोगों की प्लेट से फेंका गया भोजन का एक-एक दाना ही अमृत के समान होता है। एक गरीब मजदूर जब दिनभर भूखे रहकर मेहनत करता है और शाम को रोटी, नमक और प्याज के साथ खाता है तब उसके मुख पर जो संतोष होता है वह किसी भी व्यंजन और पकवान से अधिक मूल्यवान होता है।

आज के आधुनिक युग में जितनी रफ्तार से देश का विकास हो रहा है उतनी ही रफ्तार से हमारे देश के वृद्धाश्रमों में वृद्धों की संख्या भी बढ़ रही है। आए दिन अखबार में खबर आती है कि किस प्रकार वृद्धावस्था में पहुंचे माता-पिता पर अत्याचार होता है। प्रेमचंद की 'बूढ़ी काकी' या फिर भीष्म साहनी द्वारा लिखित 'चीफ की दावत' सिर्फ एक कल्पना नहीं है, कहानी नहीं है, अपितु समाज का यथार्थ है। जिस माता-पिता ने एक वृक्ष के समान निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों को स्नेह की छाया में पाला पोसा, कष्टों से बचाकर रखा, उनके अच्छे भविष्य के लिए अपना वर्तमान भूल गए, वही बच्चे बड़े होकर उन्हें भूल जाते हैं। भूल जाते हैं कि जिनके कारण वह खुद अस्तित्व में आए, उनका भी कोई अस्तित्व है। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो सदैव मातृत्व की छाया से, पिता के स्नेह से वंचित रहे, जो डर लगने पर मां के आंचल में छुप जाने की अनुभूति से अपरिचित हैं, पिता की उंगली पड़कर चलने से महरूम हैं। क्या वह कभी इस अनुभूति से परिचित हो पाएंगे कि किस प्रकार माता-पिता मुसीबत आने पर अपने बच्चों के लिए कवच बन जाते हैं?

इस संसार में असमानताएं बहुत हैं। किसी व्यक्ति के पास सब कुछ अत्यधिक मात्रा में है तो वहीं दूसरे के पास अत्यंत न्यूनतम मात्रा में भी नहीं। एक भरा पूरा है दूसरा बिल्कुल खाली। परंतु जीवन की गति दोनों तरफ है। और प्रकृति की गति काही परिणाम है कि कई बार जो परिपूर्ण है वह अपूर्ण लगने लगता है और जो अपूर्ण है वह परिपूर्ण का बोध करा जाता है। इसीलिए हमें सिखाया जाता है कि जीवन का सौंदर्य इसी में है कि हम अपनी प्राप्त परिस्थितियों में कृतज्ञ रहना सीखें। सुबह जब आप उठे तब मन में कृतज्ञता का भाव अवश्य लाएं कि आप सकुशल हैं। हम गर्व करें की इस संसार में एक और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के साक्षी बनेंगे, आप कृतज्ञ रहिए कि आपके पास रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और दवाई जैसी सुविधाएं हैं जो इस संसार में सबके पास नहीं होती। आप कृतज्ञ रहें कि आपके पास एक परिवार है जो आपसे प्रेम करता है, आप कृतज्ञ रहिए कि आप अभी भी पेड़ों की हरियाली को देख सकते हैं। साहित्य व्यक्ति को विनम्र और संवेदनशील बनाता है। संवेदनशील व्यक्ति में दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने की भावना होती है। साहित्य हमें सिखाता है की हर वह व्यक्ति जो आज अपने जीवन में सफल है वह सिर्फ अपने बारे में न सोचकर सर्वोदय की भावना रखे और अपने साथ-साथ दूसरों की भी सहायता करे, खासकर उनको जो खुद के लिए खड़े नहीं हो सकते। अक्सर हम दूसरों की संपन्नता देखकर अपने जीवन को अधूरा, अर्थहीन मान लेते हैं और 99 के चक्कर में पड़कर अधिक धन और अधिक सुविधाओं की तलाश करने लगते हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि सुख का संबंध मात्र भौतिक वस्तुओं से नहीं अपितु कुछ अनुभूतियों से भी होता है, संतुष्टि के भाव से भी होता है। जब एक छोटा सा पौधा भी मिट्टी से उगता है तब वह सूर्य की किरणों, जल और हवा के छोटे-छोटे उपहारों के सहारे बढ़ता है। यदि इनमें से कोई एक वस्तु भी न मिले तो उसका विकास रुक जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन भी है, छोटी-छोटी बातों की कद्र करना और उनके प्रति कृतज्ञ रहना ही जीवन को अधिक सुंदर बनाता है। ■

Kalrav July 2026_Kalrav 8/8/2026 11:46 AM Page 29

जंजीरें

गौरी तिवारी

लोगों को पसंद आती है
आसमान में उड़ती पतंग
अपने मुताबिक खींच लें
जिसकी उड़ान की बागडोर
पर खराब लगते हैं
सारे बंधनों को तोड़
बेखौफ उड़ते डेंडेलिया के फूल
जो बढ़ते हैं नई शुरुआत की ओर
लोगों को पसंद आती है
पिंजरे में कैद चिड़िया
जो भूल चुकी है अब
अपने पंखों को उड़ान देना
अपने ह्रदय की पीड़ा जताना
जीती है मजबूरन कैद होकर
मिलता है परोसा हुआ खाना
पर खराब लगते हैं
अनंत क्षितिज में उड़ते तोते
एक दिन जो पिंजरे से हो गए फुर्र
दे दिया जिसने मालिक के रचे भाग्य को धोखा
जिन्हें नहीं मिलता परोसा खाना

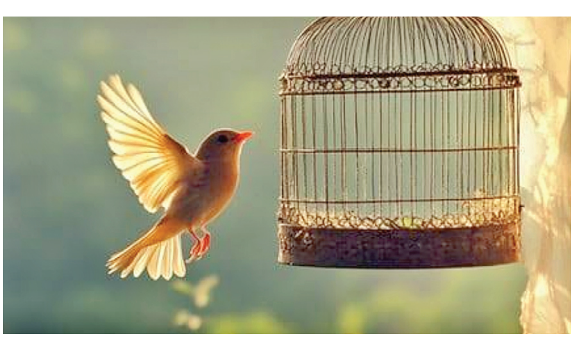

पर मिलती है स्वतंत्रता और उड़ान
लोगों को अच्छी लगती हैं
साज श्रृंगार करती स्त्रियां
जो हों अच्छी वधू पत्नी और मां
बनी रहे मूक, बधिर, दृष्टिहीन
जिन्हें बना दें अधिष्ठात्री देवी
उपाधि दें गृहस्वामिनी की
पर लोगों को खराब लगती हैं
स्त्रियां जिनके हाथ से आती है
रसोईघर के मसालों की गंध
जिनके चेहरे पर पड़ जाती हैं वर्षों की थकावट की झुर्रियां
जो दें अपने ही गृह के लिए सुझाव या लें कोई निर्णय
लोगों को अच्छी लगती हैं
कामकाजी सशक्त स्त्रियां
जो चलें घर और नौकरी दोनों साथ लेकर
हो सुंदर सुशील बुद्धिमती और कामकाजी
सूर्य के पहले उठकर निपटाए
घर के कभी न समाप्त होने वाले कार्य
जाती हो काम पर और दे घरखर्च का एक भाग
पर आए शाम को जल्दी घर
बनाए रात का खाना, दे सबको चाय
पर खराब लगती हैं स्त्रियां जो
खड़ी होती हैं अन्याय के विरुद्ध
नहीं आती किसी के शासन में
जो नहीं होती सुशील या शांत
बोलती हैं गलत को गलत
नहीं मानती बेतुकी रूढ़ियों को
जाती हैं काम पर बिना निपटाए घर के कार्य
स्वाभिमान ही है जिनका श्रृंगार ■

Kalrav July 2026_Kalrav 8/8/2026 11:46 AM Page 30

ढुलमुल वांगचुक यानी थाली के बैंगन

हिमांशु जयहिंद

राहत और स्वागत की बात है कि पिछले 25 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक अपनी पत्नी गीतांजलि की मौजूदगी में केंद्र सरकार के निचले पायदान के दो मंत्रियों के हाथ से जूस पीकर अपना अनशन समाप्त कर दिया है। आमरण अनशन के सुखांत पटाक्षेप पर जारी बयान में कहा है कि 65 सांसदों के आग्रह को सिर माथे धर अन्न जल ग्रहण करने पर राजी हुए है। मनुष्य जीवन अनमोल है, इसलिए उनके इस कदम का स्वागत हो रहा है और होना भी चाहिए। बताते हैं कि स्वयं प्रधानमंत्री ने भी सराहना की है तथा वांगचुक को चिकित्सकों की मदद से अपना खोया हुआ वजन फिर से प्राप्त करने की नेक राय दी है। वांगचुक की घोषणा से किसी को ताज्जुब नहीं हुआ। विपक्षी दलों का मानना है कि सरकार के इशारे पर बैठे थे, सरकार के कहने पर खत्म कर दिया। धुर कांग्रेसी नेता रहे सोनम वांग्याल के पुत्र सोनम बांगचुक पर्यावरण प्रहरी है और अपनी दूसरी पत्नी गीतांजलि के साथ मिलकर लद्दाख के दुर्गम इलाकों में शिक्षा और पर्यावरण रक्षा को लेकर एक संस्थान चलाते हैं।

आभासी जगत से जन्मी कॉकरोच जनता पार्टी की जमीनी गतिविधियां बढ़ी तो वांगचुक भी जुड़े और उन्होंने कॉकरोचों को समर्थन देने का ऐलान किया तथा भूख हड़ताल पर बैठ गए। पूर्व में बिना किसी बुलावे के जिस तरह वे अपने स्वयं के निर्णय से पार्टी को समर्थन देने आए ठीक उसी तरह बीती रात बिना किसी सलाह मशविरा के उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। इसमें कोई बुराई नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर यह स्वतंत्रता सभी को है। लेकिन जब व्यक्तिगत निर्णय पर सामूहिक बोध का दावा किया जाने लगे तो जाहिर है की सवाल भी खड़े होंगे। अनशन समाप्ति के बाद उन्होंने जो बयान जारी किया है उसकी भाषा के निहितार्थ खोजे जा रहे हैं। चिंतन मनन, बहस विमर्श के साथ खंडन मंडन भी हो रहा है। बयान की भाषा चीख-चीख कर कह रही है की सब कुछ 'स्क्रिप्टेड' है। मैं स्वयं भाषा से जुड़ा हुआ हूं। भाषा माध्यम है — सूचना का और संवेदना का। सूचना के लिए सरल, सीधी और इकहरी भाषा चाहिए। उससे वही अर्थ निकले जो लिखा या कहा गया हो! गणित और कानून की भाषा ऐसी ही होती है। पर संवेदनाएँ अतल, असीम, अनंत, अरूप और अमाप्य होती हैं। भाषा को उनकी गहराइयाँ, ऊँचाइयाँ और अरूप भावनाएँ व्यक्त करनी होती हैं। इसलिए मीरा दर्द में इतना ही कह पाती हैं – मेरो दर्द न जाने कोय।

परन्तु भाषा हार नहीं मानती। वह अकथ्य को कहने के लिए कुछ-न-कुछ तरीके खोज लेती है। संवेदना की अतल गहराइयों तक पहुँचने के लिए उसे दिव्य प्रक्षेपास्त्र बनाने पड़ते हैं। कभी शब्द को प्रक्षेपास्त्र बनाना पड़ता है, कभी पदबंध को तो कभी पूरे वाक्य को।

शब्द को प्रक्षेपास्त्र बनाएँ तो उपमान या प्रतीक बनता है। पदबंध को सुदूर अर्थ तक प्रक्षेपित किया जाए तो उसे बहुव्रीहि समास या मुहावरा कहते हैं। और वाक्य को दूरभेदी बनाएँ तो उसे सूक्ति, अन्योक्ति, लोकोक्ति या समासोक्ति कहते हैं।

किसी मोटे को **मोटा** कहने में वह बात नहीं है, जो उसे **हाथी** कहने में है ; मूर्ख को गधा कहने में है, शिशु को फूल कहने में है या सुंदरी को हरसिंगार कहने में है। इन्हें प्रतीक कहें या उपमान, ये दिव्यास्त्र हैं जो किसी के गुण को अनंत फैलाव दे देते हैं। ये शब्द या पद जब एकत्र होकर पदबंध या मुहावरा बनते हैं और एक वाक्य के अंग बनते हैं तो इनकी धार देखने योग्य होती है। किसी **ढुलमुल** को **थाली का बैंगन** या **बेपैंदी का लोटा** कहने में जो बात है, अकारण बात बढ़ाने को तिल का ताड़ बनाना कहने में जो बात है, वह सरल अभिव्यक्ति में कहाँ! ये भी भाषा के दिव्यास्त्र हैं।

भाषा के दिव्यास्त्र अनंत हैं ; क्योंकि भाषा ऐसी दिव्य सुंदरी है जो संसार के सभी परिधानों को धत्ता बताकर अपने लिए नित नए परिधान खोज लेती है। वाक्य-रचना में जब वह तीखी मिर्च-सी तेज और प्रभावी हो जाती है तो सूक्ति कहलाती है। है तो वह उक्ति ही, परंतु उसकी चुस्ती, कलात्मकता और संक्षिप्तता के कारण हम उसे सूक्ति कहते हैं। थोड़े में बहुत कहना या गागर में सागर भरना –यह सूक्ति की करामात है।

और जब कोई उक्ति अपने संकेतों के द्वारा खुद अपने आप को नहीं व्यक्त करती बल्कि अपने बहाने से औरों पर वार करती है ; 'कहना बेटी को सुनाना बहू को' के अंदाज में जब बातें करती है तो उसे अन्योक्ति कहते हैं।

Kalrav July 2026_Kalrav 8/8/2026 11:46 AM Page 31

बिहारी की एक अन्योक्ति प्रसिद्ध है। कच्ची उम्र की नई पत्नी के संग विलास में डूबे राजा जयसिंह को जब कोई नहीं चेता सका तो बिहारी की इस एक अन्योक्ति ने चेताया। उन्होंने लिखा –

नहीं पराग नहिं मधुर मधु, नहीं विकास इहिं काल।
अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल।

कहते हैं राजा जयसिंह इस दिव्यास्त्र की चोट से दरबार में लौटे। यह अन्योक्ति है। इसी की एक दुधारी बहन है– समासोक्ति। वह दोनों तरफ धार रखती है। अपने लिए भी जीती है और औरों पर भी दूर तक मार करती है। जब पद्मावती की सखियाँ पद्मावती को कहती हैं —

ए रानी ! मन देखु बिचारी। एही नैहर रहना दिन चारी।

वे केवल अपने मायके में रहने की बात नहीं कर रही, अपितु इस नश्वर संसार में रहने की भी बात कर रही हैं ।

अन्योक्ति और समासोक्ति कितना भी संकेत उठा लें, किंतु वे दोनों किसी एक लक्ष्य से बँधी होती हैं। परंतु **लोकोक्ति** स्वतंत्र है, मुक्त विचरण करती है और लोगों की जुबान पर भी विहार करती है। इसलिए उसे **कहावत** भी कहते हैं। जब कोई सांकेतिक उक्ति स्वयं अपना अर्थ न देकर किसी और तरफ इशारा करती है तो उसे लोकोक्ति कहते हैं। यह स्वयं में पूरा वाक्य होती है। यह वाक्य पर निर्भर नहीं होती बल्कि किसी कथन को पुष्ट करती है या उसका समर्थन करती है। जैसे — **अधजल गगरी छलकत जाय**। कोई अपटु, अकुशल व्यक्ति कुशलता पर बढ़-चढ़कर बातें करने लगे तो बस इतना ही कहना काफ़ी है — **थोथा चना बाजे घना**।

कुल मिलाकर परीक्षाओं में गड़बड़ी और उसकी जवाब देही तय करने के लिए वर्तमान शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित वांगचुक की भूख हड़ताल बगैर लक्ष्य प्राप्ति के समाप्त हो गई है। उन पर सरकारी आंदोलन-जीवी होने के आरोप हैं। उनके विदेशी फंडिंग का भी मामला बताया जाता है। उनकी ओर से एक बयान जारी किया गया है। देश, काल परिस्थिति के हिसाब से बयान की भाषा, विषय- वस्तु, भाव-भंगिमा आदि के आधार पर साधारण भाषाई समझ यही कहती है की दूसरे कोने में लुढ़का दिए जाने के डर से बैगन ने खुद ही करवट बदल ली है। हालांकि जंतर मंतर पर बैठे कॉकरोच दल ने वांगचुक के निर्णय से अपने को अलग किया है। लेकिन सरकारी अमलों की देह भाषा बता रही है कि केंद्र की सरकार को भी थोडी राहत मिली है।

सरकार के संतुलनकारों को लगता है राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, और गाड़ियों में मिलावटी एथेनॉल का मामला नेपथ्य में चला गया है। शिक्षा के मुद्दे पर हो रही विपक्षी एकता को तहस-नहस करने में लगभग कामयाबी मिल गई है। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर मोहर लग चुकी है। झारखंड में पीसीएस की परीक्षा देने गए प्रतियोगी छात्र निराश होकर एक बार फिर अपने-अपने घरों को लौट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। संघ और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों की मौजूदगी में अयोध्या में सैकड़ो संत बैठक कर राम मंदिर चढ़ावा चोरी के कथित सरगना संपत बंसल को ससम्मान फिर से ट्रस्ट में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने के लिए रास्ता बनाने में जुट गए हैं। नीट धांधली के मुख्य आरोपी मुखिया को सीबीआई ने क्लीन चिट दे ही दिया है।

हम सभी जानते हैं आंदोलन के लिए दिल्ली सहित देश के अन्य हिस्सों में बच्चे सड़क पर उतरे, पुलिस की लाठी खाए। वे एक बार और ठगे गए। अब आश्वासनों की खेती होगी, बड़े-बड़े वादों के बीज बोये जाएंगे। अन्ना, अरविंद, वांगचुक की नस्ल का कोई नया बैगन तलाश लिया जाएगा जो जरूरत के हिसाब से थालियों में लुढ़कने लुढ़काने योग्य होगा।

जनता बहुत समझदार है। जनता द्वारा चुने गए नेता और अधिक समझदार हैं। पढ़े लिखो की समझदारी पर मुझे कोई शक नहीं है। आइए, गोरख की 'समझदारों का गीत' कविता पढ़ते हैं-

हवा का रुख़ कैसा है, हम समझते हैं
हम उसे पीठ क्यों दे देते हैं, हम समझते हैं
हम समझते हैं ख़ून का मतलब
पैसे की क़ीमत हम समझते हैं
क्या है पक्ष में विपक्ष में क्या है, हम समझते हैं
हम इतना समझते हैं
कि समझने से डरते हैं और चुप रहते हैं
चुप्पी का मतलब भी हम समझते हैं
बोलते हैं तो सोच-समझकर बोलते हैं हम
हम बोलने की आज़ादी का, मतलब समझते हैं
टुटपुँजिया नौकरियों के लिए
आज़ादी बेचने का मतलब हम समझते हैं
मगर हम क्या कर सकते हैं
अगर बेरोज़गारी अन्याय से तेज़ दर से बढ़ रही हो
हम आज़ादी और बेरोज़गारी दोनों के
ख़तरे समझते हैं, हम ख़तरों से बाल-बाल बच जाते हैं
हम समझते हैं, हम क्यों बच जाते हैं, यह भी हम समझते हैं
वैसे हम अपने को किसी से कम
नहीं समझते हैं, हम स्याह को सफ़ेद और
सफ़ेद को स्याह कर सकते हैं
हम चाय की प्यालियों में
तूफ़ान खड़ा कर सकते हैं
करने को तो हम क्रांति भी कर सकते हैं
अगर सरकार कमज़ोर हो
और जनता समझदार, लेकिन हम समझते हैं
कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं
हम क्यों नहीं कुछ कर सकते हैं
यह भी हम समझते हैं। ■

Kalrav July 2026_Kalrav 8/8/2026 11:46 AM Page 32

घोषित इमरजेंसी बनाम अघोषित आपातकाल

वरुण कुमार पांडे

कहते हैं इतिहास सब कुछ दर्ज करता है। निरंतर चल रही घटनाओं को साक्षी भाव से सहेज कर रखता है और समय आने पर आईने की तरह ब्लैक एंड व्हाइट में दिखा भी देता है। महीन से महीन करतूतो को भी इतिहास समय आने पर उजागर कर देता है और इतिहास के बारे में कहा यह भी जाता है कि इतिहास समय के घूमते पहिए के साथ कभी ना कभी अपने को दोहराता भी है।

आपातकाल यानी साधारण शब्दों में कहें तो आफतकाल। किसी भी सभ्य समाज के लिए आपातकाल खुशगवार, सुकूनदेह शब्द नहीं है। आपातकाल में प्रचलित नागरिक अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जाता है और शासन सत्ता में बैठे लोग निरंकुशता के साथ अपनी तानाशाही अपनी मनमानी करने का आधार गढ़ लेते हैं।

भारत ने आजादी के बाद 21 महीनों तक घोषित आपातकाल का दंश झेला है। उस दौर में विपक्षी नेताओं को कैद में बंद कर दिया गया था। लोकतंत्र के चौथे खंबे प्रेस की आजादी पर प्रतिबंध लगाया गया था। लोकतंत्रात्मक गणराज्य की सरकार अध्यादेशों के सहारे चलाई जा रही थी।

सत्तर के दशक का यह वह समय ऐसा था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को देश का पर्याय भी कहा जाने लगा था। किसी और ने नहीं बल्कि उनकी पार्टी के उस समय के कवि हृदय अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने कहा था, 'इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा'। केवल श्री बरुआ ही नहीं कांग्रेस के तमाम बड़े नेता श्रीमती गांधी की खुशामद में तमाम तरह के कसीदे पढ़ रहे थे।

12 जून, 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाजवादी नेता राजनारायण की चुनाव याचिका पर फैसला सुनाते हुए श्रीमती गांधी के रायबरेली से लोकसभा चुनाव को अवैध घोषित करने के साथ ही उनपर अगले छह वर्षों तक कोई भी चुनाव लड़ने के लिए रोक लगा दी थी। इस फैसले को लेकर कांग्रेस पार्टी में दो तरह की राय थी। एक तो यह कि श्रीमती गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक किसी वरिष्ठ नेता को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला श्रीमती गांधी के पक्ष में आने पर पद त्याग कर सत्ता वापस श्रीमती गांधी को सौंप दे। दूसरी राय सुप्रीम कोर्ट में अपील के साथ ही फैसला आने तक श्रीमती गांधी के

प्रधानमंत्री बने रहने के पक्ष में थी। विदेशी लेखिका कैथरीन फ्रैंक ''इंदिरा : दि लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी' में लिखती हैं, "इस सबंध में श्रीमती गांधी ने अपने करीबी विधि विशेषज्ञ और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे से कहा, 'मुझे त्यागपत्र देना चाहिए।' जवाब में श्री रे ने कहा कि 'हड़बड़ी में उन्हें ऐसा कोई फैसला नहीं करना चाहिए।'

कुलदीप नैयर अपनी पुस्तक 'इमरजेंसी की इनसाइड स्टोरी' में लिखते हैं कि श्रीमती गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद अपने मंत्रिमंडल के तीन वरिष्ठ सदस्यों-जगजीवन राम, यशवंतराव चव्हाण और स्वर्ण सिंह से पूछा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक उनका पद पर बने रहना वाजिब होगा! तीनों ने मन की बात मन में मारते हुए कहा कि अगर वह त्यागपत्र देती हैं तो देश में तबाही मच जाएगी। बकौल श्री नैयर, "जगजीवन राम ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करना चाहिए।

पुपुल जयकर 'इंदिरा गांधी : एक जीवनी' में लिखती हैं कि उस समय कांग्रेस के भीतर अफवाहों, नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और दोमुहीं बातों का दौर शुरू हो गया था। श्रीमती गांधी से मिलने वाले कांग्रेस के बड़े नेता, वरिष्ठ मंत्री एक तरफ तो उनके प्रति अटूट श्रद्धा और आस्था व्यक्त कर रहे थे, दूसरी तरफ पर्दे के पीछे वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में अपने लिए संभावनाएं भी तलाशने में लगे थे।

जगजीवन राम, यशवंतराव चव्हाण, सरदार स्वर्ण सिंह के पक्ष में लॉबीइंग भी शुरू हो गई थी। वह लिखती हैं, "कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष देव कांत बरुआ ने श्रीमती गांधी के सामने सुझाव रखा कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक श्रीमती गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएं और वे (बरुआ) उस समय तक के लिए प्रधानमंत्री। फैसला श्रीमती गांधी के पक्ष में आने पर वह उनके लिए प्रधानमंत्री का पद खाली कर देंगे।" लेकिन कहते हैं कि जिस समय प्रधानमंत्री आवास पर यह चर्चाएं चल रही थीं, तभी गुड़गांव में अपनी मारुति फैक्ट्री से लंच के समय वहां आए इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी ने अपनी मां को किनारे ले जाकर समझाया कि उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए। प्रधानमंत्री के रूप में (चाहे वह कार्यवाहक या अल्पकालिक ही क्यों न हो) पार्टी के किसी भी नेता पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यही राय श्रीमती गांधी के विश्वासपात्र अतिरिक्त निजी सचिव आर के (राजेंद्र कुमार) धवन की भी थी। संजय और धवन ने उन्हें समझाया कि त्यागपत्र देने के बाद पिछले आठ वर्षों में खासी मशक्कत से उन्होंने पार्टी और सरकार में अपनी जो निष्कंटक स्थिति हासिल की है, उसे वे तुरंत खो देंगी। इंदिरा गांधी अपने बेटे संजय, विश्वस्त करीबी सिद्धार्थ शंकर रे और धवन के तर्कों से सहमत हो गईं। उन्होंने तय किया कि इस्तीफा देने के बजाय वह इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली बीस दिनों की मोहलत का इस्तेमाल करते हुए इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी और पद पर बनी भी रहेंगी। बकौल पुपुल जयकर, अपने सुझाव पर इंदिरा गांधी की अनुकूल या कहें उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया नहीं मिलती देख श्री बरुआ निराश हुए, डर गए और 'इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा' कहने लगे।

कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में संसद के दोनो सदनो के 518 सदस्य की ओर से पारित प्रस्ताव में कहा गया कि इंदिरा गांधी का नेतृत्व देश के लिए अपरिहार्य है। प्रस्ताव जगजीवन राम ने पेश किया जबकि अनुमोदन यशवंतराव चव्हाण ने किया था। उस समय प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव रहे बिशन टंडन अपनी पुस्तक 'पी एम ओ डायरी (भाग एक) दि इमरजेंसी' में लिखते हैं, "बैठक में श्री चव्हाण ने कहा था, ''भारत (इंडिया) को जो होता है, वह इंदिरा को होता है और जो इंदिरा गांधी को होता है, वह भारत को होता है।'' इसी बैठक की अध्यक्षता करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने थोड़ा और आगे बढ़ते हुए कहा था, 'इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा' यानी 'इंदिरा भारत हैं और भारत इंदिरा'।"

और फिर शुरू हुआ था देशव्यापी भक्ति प्रदर्शन। राज्यों के मुख्यमंत्री ने अपने-अपने राज्य से इंदिरा को महान बताते हुए उनके

पक्ष में प्रस्ताव पारित किए गए वही देश भर से कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं को जूटा कर अपना अपना नंबर बढ़ने लगे।

लोग बताते हैं की पूरी दिल्ली श्रीमती गांधी के समर्थन और उनमें आस्था व्यक्त करने वाले पोस्टरों, कटआउटों से पट गयी थी।

20 जून 1975 को राजधानी दिल्ली में एक विशाल रैली आयोजित कर श्रीमती गांधी के पक्ष में शक्ति प्रदर्शन किया गया। इस रैली में श्रीमती गांधी का पूरा परिवार (दोनों बेटे-राजीव और संजय गांधी और दोनों बहुएं-सोनिया और मेनका गांधी) उनके साथ खड़ा था। इस रैली में व्यक्ति पूजा और चाटुकारिता की हदें पार करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष देव कांत बरुआ ने एक शेर पढ़ा था,

"इंदिरा तेरी सुबह की जय, इंदिरा तेरी शाम की जय,

इंदिरा तेरे नाम की जय, इंदिरा तेरे काम की जय।" लोग दावा करते हैं कि इस रैली में 10 लाख से अधिक लोग जुटे थे।

श्रीमती गांधी के खिलाफ पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर भी गोलबंदी हो रही थी। प्रमुख विपक्षी पार्टियां देश में व्याप्त अराजकता महंगाई भ्रष्टाचार को आगे कर कांग्रेस की सत्ता उखाड़ने फेंकने का आह्वान कर रही थी।

कुलदीप नैयर 'इमरजेंसी की इनसाइड स्टोरी' (पृष्ठ 44) में लिखते हैं, "श्रीमती गांधी ने रैली में कहा, कुछ विदेशी शक्तियां और निहित स्वार्थी तत्व न सिर्फ मुझे पद से हटाना चाहते हैं बल्कि जान से भी मारना चाहते हैं। विपक्ष इन शक्तियों से मिला हुआ है। इन तत्वों को मीडिया का समर्थन भी हासिल है। तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर झूठ फैलाया जा रहा है। सवाल यह नहीं है कि मैं पद पर रहूं या ना रहूं, सवाल राष्ट्रीय हितों की रक्षा का है।"

रैली के बाद कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें दिए एक पृष्ठ के ज्ञापन में कहा कि श्रीमती गांधी के त्यागपत्र से न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि राज्यों में भी अस्थिरता फैल जाएगी। इंदिरा गांधी को आशंका थी कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए देश में बड़े उलट फेर और गड़बड़ियां फैलाने में जुटी है। इसी तरह के शक के आधार पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा को हटा दिया गया और उनकी जगह दिल्ली के चाटुकार नारायण तिवारी को प्रदेश की कमान दे दी गई। नई दिल्ली तिवारी के बारे में चर्चा थी कि वह संजय गांधी की चापलूसी में दिन-रात लगे रहते थे।

दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण की ऐतिहासिक रैली के बाद आधी रात को आपातकाल की घोषणा हुई। श्रीमती गांधी को जल्दी ही यह एहसास हो गया कि भारत की लोकतांत्रिक आजादी को कानून के जरिए लंबे समय तक निलंबित नहीं किया जा सकता इसलिए उन्होंने देश की जनता को एक ही जादू कड़ी मेहनत, दूर दृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासन का प्रण दिलाते हुए सभी वर्गों के विकास हेतु 20 सूत्री कार्यक्रमों का सूत्रपात किया तथा लोकतंत्र बहाली के लिए देश में आम चुनाव की घोषणा की।

घोषित आपातकाल के पांच दशक पूरा होने के बाद देश में अमृतकाल चल रहा है।

उन दिनों की तुलना आज के 'अमृतकाल' से की जाए तो तो लगता है कि हम अमृत काल में नहीं बल्कि एक अघोषित आपातकाल के दौर में जी रहे हैं। आपातकाल में बोलने की आजादी नहीं थी, आज के दौर में भी अभिव्यक्ति पर पहरा है। आपातकाल में प्रेस की आजादी जप्त कर ली गई थी, आज मुख्य धारा की मीडिया को जर-खरीद गुलाम बना लिया गया है। खान पान, रहन-सहन, वेशभूषा, सरकार के इशारे पर नियंत्रित की जा रही है। धार्मिक आजादी पर अंकुश लगाने की कोशिश जारी है। यहां तक कि प्रेम पर भी सरकार समर्थित संगठनों का पहरा है। चाटुकारिता के मामले में आज का अमृत काल तब के आपातकाल को लगातार बौना साबित कर रहा है।

प्रधानमंत्री की प्रशस्ति और चाटुकारिता के मामले में भाजपा के अध्यक्ष रहे जगत प्रकाश नड्डा सहित तमाम बड़े और जिम्मेदार नेताओं ने देवकांत बरुआ सहित कांग्रेस के अन्य नेताओं को बहुत पीछे छोड़ दिया है। उन्हें विश्व गुरु, देवताओं के भी नेता, युग पुरुष, देव तुल्य, देव दूत, साक्षात भगवान, सुपर ह्यूमन तक कहा जा रहा है। और तो और श्री मोदी ने स्वयं भी खुद को नान बॉयोलॉजिकल उत्पत्ति बताते हुए कहा है कि भगवान ने उन्हें यहां किसी खास इरादे से भेजा है। राम मंदिर, अयोध्या में श्रद्धालुओं के दान-चढ़ावे में चोरी के आरोपों से घिरे, विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष एवं श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत बंसल ने तो श्री मोदी को देश का राजा और इस बहाने विष्णु का अवतार भी कह दिया।

कुल मिलाकर घोषित आपातकाल का दौर काट चुके लोगों की एक बड़ी संख्या अभी भी देश में मौजूद है। पुराने लोगों से बात करने पर पता चलता है की सिक्के के दो पहलू होते हैं। लोकतांत्रिक अधिकारों पर प्रतिबंध की शिकायत तो वे करते हैं लेकिन लगे हाथों, वे उसे दौर की अच्छाइयां भी गिनाते हैं। इमरजेंसी के दौरान अमूमन लेट चलने वाली रेलें टाइम से चलने लगी थी। बाजार में घटतौली, मिलावट खोरी मूल्य वृद्धि पर पूरी तरह से अंकुश हो गया था। पुलिस थानों पर आम जन की शिकायतें तुरंत संज्ञान की जाती थी। हड़ताल धरना प्रदर्शन के कल्चर पर रोक से स्कूल कॉलेज समय से चलने लगे थे। सरकारी दफ्तरों में उपस्थित नियमित हो गई थी। एक जवाब देही का वातावरण निर्मित हुआ था।

आज के समय में हम देखें तो आए दिन भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं। दिल्ली के अस्पतालों में हजारों करोड़ों का घपला उजागर हुआ है। किसी भी सरकारी ऑफिस में बिना लेनदेन के कोई काम नहीं हो रहा है। धर्म जाति संप्रदाय के नाम पर एक दूसरे को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस प्रताड़ना भी बढी है। एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई को मान्यता दी जा रही है। लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने के आरोप लग रहे हैं। यह सब कुछ एक तरह से अघोषित आपातकाल की तर्ज पर हो रहा है। ■

जल ही जीवन है

आइये पानी बचाने का संकल्प लें

सहयोग

एक सामूहिक प्रयास

सहयोग द्वारा जनहित में जारी

Kalrav July 2026_Kalrav 8/8/2026 11:46 AM Page 36

RNI-UPHIN-2006/18176 Postal Regd. No. UP/GBD-199/2014-16 ISSN 2395-3829

अपने और अपने आसपास के लोगों का बचाव करें

तबीयत ठीक न होने पर घर पर ही रहें

अपने चेहरे, नाक और मुंह को छूने से बचें

खांसी-जुकाम वाले लोगों से 1.5 मीटर की दूरी बनाएं

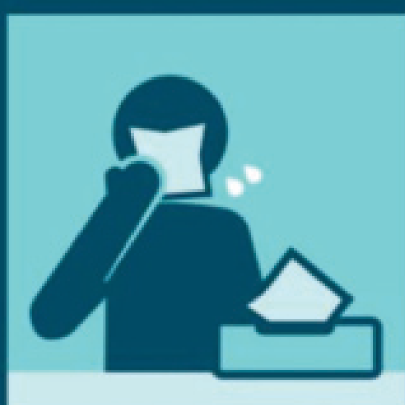

खांसी-जुकाम होने पर मुंह ढककर रखें

हाथों को लगातार धोते रहें

सहयोग

एक सामूहिक प्रयास

सहयोग की ओर से जनहित मे जारी